Announcement re Government Business

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 29th March, 1976, will consist of :

(1) Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(a) The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1976.

(b) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1976.

(2) General Discussion on the Tamil Nadu Budget for 1976-77.

(3) Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(a) The Tamil Nadu Appropriation Bill, 1976.

(b) The Tamil Nadu Appropriation (No. 2) Bill, 1976.

(4) General Discussion on the Gujarat Budget for 1976-77.

(5) Consideration and return of the Gujarat Appropriation Bill, 1976, as passed by Lok Sabha.

(6) Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(a) The Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Bill, 1976.

(b) The Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Bill, 1976.

(7) Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

(a) The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill, 1976.

(b) The Beedi Workers Welfare Cess Bill, 1976.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, **Mr. Deputy Chairman** *in the Chair.*

Resolution regarding formulation of a scheme to ensure a remunerative price to growers of each agricultural commodity— *Contd.*

श्री कल्प नाथ (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ने मुझे खेती की पैदावार के दामों के संबंध में बोलने का अवसर दिया है। मैं गुलाब राव पाटिल साहब को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हिन्दुस्तान के लाखों किसानों की परेशानियों को आज संसद के सामने रखा है। आज के दौर में हमारा देश बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के दौर से गुजर रहा है। महान देश की महान नेता इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने समाजवाद देश निर्माण की हरियाली घाटी में पहुंचने का फैसला किया है। देश की करोड़ों करोड़ कुचले, दबे पिसे पिछड़े लोगों ने हजारों वर्ष बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में यह महसूस किया है है कि राजगद्दी एवं राजनीति के हथियार से गरीबी की दलदल में धंसे करोड़ों करोड़ लोगों को निकाला जा सकता है। देश के करोड़ों करोड़ इंसानों को सदियों के कर्ज से मुक्ति दिला कर करोड़ों बेघर इंसानों को घर दिला कर करोड़ों इंसानों को धन धरती का हिस्सेदार बना कर पहली बार प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने पूंजीवाद एवं सामंतवाद के पहाड़ को बीस सूत्री कार्यक्रम के डाइनामाइट

से तोड़ना प्रारम्भ किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति समाजवाद के महान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मगर देश की रीढ़ किसान गांव एवं खेती के समन्वित विकास के लिए प्रधान मंत्री को सोचना होगा एवं खेती तथा किसानों को बर्बाद होने से बचाना होगा। किसान गन्ना पैदा करता है। हम सरकार के गन्ना के दाम के विषय एवं गन्ने की चीनी के मूल्य पर विचार करें। चीनी हमारे देश की सब से बड़ी एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री है और हमारे देश में गन्ने की उपज की वजह से चीनी मिलें आज दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आज गन्ना 12, 18 रुपये क्विंटल के दाम से खोइया 18 रुपये क्विंटल के दाम से एवं सिटकी लकड़ी बीस रुपये क्विंटल के भाव से बिक रही है। *क्या इस से भी बड़ी किसानों की लूट दुनिया* के किसी देश में हो रही है।

गन्ने के दाम का सवाल देश में सन् 1931 से एक बड़ा सवाल रहा है। इस देश में किसान गन्ने की उपज करता था। इस से किसान अपना जीवन निर्वाह करते थे एवं करोड़ों रुपयों का गुड़ वह बेचता था।

सन् 1933 में पहली बार गन्ने का दाम तय किया गया, इसके बाद 1934 में प्रान्तीय सरकारों ने गन्ने का दाम तय करने के लिए गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया एवं न्यूनतम गन्ना की कीमत निर्धारित की। 1937 एवं 1938 में केन्द्रीय सरकार ने यू०पी० और बिहार की सरकारों को यह शक्ति दी कि वे कानून बना कर गन्ने का न्यूनतम दाम तय करें। 1942 से 1948 तक केन्द्रीय सरकार ने गन्ने पर खुद नियंत्रण रखा और फिर 1950 में गन्ने की स्टैचुटेरी प्राइस तय करने का कानून बनाया और इस के बाद बहुत सी कमेटियां बनीं। कमेटियों का काम चीनी मिलों की रक्षा करना एवं गन्ने का दाम तय करना था। 1958-59 में लिंकिंग फार्मूला बना। इसके बाद रिक्वरी के आधार पर गन्ने का दाम तय करने का फार्मूला केन्द्रीय सरकार ने बनाया। भार्गव कमीशन ने भी गन्ने के दाम को तय करने का कोई मापदंड नहीं बताया।

कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने है। कृषि मूल्य आयोग ने 1975-76 की रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल गन्ने का जो दाम तय था उससे इस साल स्टैचुटेरी प्राइस एक रुपया ज्यादा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में साढ़े चौदह रुपया दाम दिया जायेगा। पूर्व में साढ़े तेरह रुपया दिया जायेगा। जब आपने यह सिद्धांत मान लिया है कि रिक्वरी के आधार पर गन्ने का दाम तय होगा तो फिर समझ में नहीं आता कि दाम कैसे तय हो रहा है। पूर्व को रिक्वरी पौने दस प्रतिशत हो रही है। पश्चिम वालों की रिक्वरी कम हो गयी है लेकिन पूर्व वालों के गन्ने का दाम सवा बारह रुपया एवं पश्चिम वालों का सवा तेरह रुपया क्यों? पंजाब की सरकार ने गन्ने का दाम 14 रुपये 35 पैसे तय किया जब कि दक्षिणी हिन्दुस्तान में कोआपरेटिव सेक्टर में चलने वाली मिलों की रिक्वरी दस प्रतिशत है। वहां गन्ने का दाम 18 रुपये क्विंटल मिलता है। कृषि मूल्य आयोग पिछले साल की अपेक्षा इस साल एक रुपया ज्यादा दाम बढ़ाने की बात करता है। तो उसके अनुसार साढ़े तेरह रुपया का भाव हमें मिलना चाहिए। पिछले साल यह भी कहा गया था कि अगर खुले बाजार में चीनी 400 रुपये क्विंटल बिकेगी तो चौदह रुपया पचास पैसे का भाव दिया जायेगा। आज खुले बाजार में चीनी का मूल्य साढ़े चार सौ रुपये क्विंटल है और थोक में चार सौ पच्चीस रुपये, तो फिर किस आधार पर हमें 12 रुपये क्विंटल का भाव दिया गया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन ने कहा था अपनी मीटिंग में कि हम साढ़े चौदह रुपये गन्ने का दाम क्विंटल के भाव से देंगे यदि खुले बाजार में चीनी चार सौ रुपये क्विंटल के भाव में बिके। पिछले पांच सालों में गन्ना के मिल मालिकों को सरकार ने 200 करोड़ रुपयों का रिलीफ दिया। पिछले सात दिसम्बर को खाद्य मंत्री एवं चीनी मिल-मालिकों की मीटिंग में चीनी मिल-मालिकों ने मान लिया था कि साढ़े चौदह का भाव वे देने को तैयार हैं, लेकिन क्रेडिट स्क्वीज की पालिसी को ठीक किया गया। लेवी शुगर का प्राइस बढ़ाया जाये।

आज किसान को अपना गन्ना रिजर्व एरिया में बेचने के लिये मजबूर किया जाता है; क्योंकि ऐसा होने पर वह अपने गन्ने का दाम बढ़ा नहीं पायेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने को पैदा करने के लिये किसान जेठ की चिल-चिलाती धूप में जान को जोखिम में डाल कर खून-प

[श्री कल्पनाथ]

एक कर के नौ महीने परिश्रम करता है एवं जब गन्ना पैदा होता है तो किसान के गन्ने की लूट शुरू हो जाती है। गन्ना को पैदा करने के लिए किन चीजों की जरूरत है ट्रैक्टर या बैल? ट्रैक्टर सरकार के कारखाने से पचास हजार में मिलता है। बैलों की जोड़ी तीन हजार या चार हजार रुपया जोड़ी है। ड्राइ खाद 140 रु० बोरी मिलती है। सिचाई की दर दूनी हो गई है। 15 रु० हार्स पावर की बिजली मिलती है। डीजल की कीमत तिगुनी बढ़ गई। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी साढ़े चार रुपया मजदूर की निर्धारित हो गई। क्या इतने महंगे दाम के ट्रैक्टर, महंगी बिजली, महंगे उर्वरक, महंगे डीजल, महंगी मजदूरी का इस्तेमाल कर किसान गन्ने की खेती कर सकता है?

सरकार का कहना है कि माडर्न टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किसानों को अधिक अन्न उपजाओ में करना चाहिए। यदि 5-6-8-10 एकड़ खेत जोतने वाला किसान यदि माडर्न टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करना चाहे तो क्या वह पचास हजार रुपये का ट्रेक्टर खरीद सकता है? क्या 140 रु० बोरी ड्राई खाद का इस्तेमाल कर सकता है? क्या 15 हार्स पावर की बिजली का इस्तेमाल कर सकता है यदि यह मान भी लिया जाय कि वह सरकार की अपील पर महंगी टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करे तो क्या इतनी मेहनत के बाद यदि उसका गन्ना 12 रु० क्विंटल के हिसाब से लिया जाए एवं खोइया 18 रु० क्विंटल के हिसाब से बेचा जाए एवं सूखी लकड़ी 20 रु० क्विंटल के हिसाब से बेची जाए तो क्या किसानों के दिल में जल रहा आशा का दीप न बुझ जाएगा? क्या उनके मन में उग रहा देश निर्माण का बीज अंकुरित होकर नहीं नष्ट हो जाएगा? विश्व के महान् दार्शनिक मार्क्स ने कहा कि मजदूर क्रान्ति के अग्रवा होंगे। लेनिन ने कहा मजदूर एवं किसान दोनों मिलकर क्रान्ति की अगुवायी करेंगे। और माओत्सुंग का कहना है कि किसान ही किसी देश की क्रान्त का नेतृत्व कर सकता है। सन् 1947 के बाद देश के क्रान्तिकारी भगत-सिंह एवं चन्द्रशेखर आजाद, सरदार प्रतापसिंह कैरों एवं बंशीलाल हैं, जिन्होंने अधिक अन्न उपजा कर पंडित नेहरू एवं गांधी के देश निर्माण के सपनों को साकार किया है। भाग्य से दोनों ही किसान के बेटे हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, गन्ना, कपास, जूट पैदा करने वाले किसानों को उत्साहवर्द्धक दाम दिया जाए, किसान द्वारा पैदा किये गये गेहूं का दाम 105 रु० क्विंटल कृषि मूल्य आयोग ने निर्धारित किया है एवं उन्नतिशील बीज का दाम 275 रु० प्रति क्विंटल है। ऐसा क्यों याद रखें, यदि किसानों की क्रयशक्ति खत्म होगी तो बिड़ला, टाटा, डालमिया के कारखानों में बनने वाली वस्तुएं बाजार में पड़ी रह जायेंगी। कोई खरीददार नहीं होगा। किसान, गांव की खेती की चतुर्दिक तरक्की पर ही मुट्ठी भर पूंजीपतियों की भी तरक्की सम्भव है।

आज चीनी के कारण भारत को विदेशों से 700 करोड़ का फारन एक्सचेंज मिला है। यदि सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर ले एवं किसानों को 20 रुपया क्विंटल के हिसाब से गन्ने का दाम दे तो किसान इतना गन्ना पैदा करे कि 21 सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, इस वर्ष भी सरकार को 1 हजार करोड़ का गल्ला विदेशों से मंगाना होगा। यदि सरकार इसी 1 हजार करोड़ को किसानों को उर्वरक पर सबसिडी दे दे तो एक भी छटांक अनाज विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा।

खेतों में पैदा होने वाली एवं कारखानों में पैदा होने वाली चीजों का दाम बांधा जाये। जो सामान कारखाने में जितनी लागत से पैदा हो वह लागत के ड्योढ़े के अन्दर बिके एवं खेती की पैदावार के दाम में एक फसल से दूसरी फसल के बीच दामों को उतार-चढ़ाव सात गुना दाम के अन्दर हो तो हम एक गतिशील अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकेंगे।

कृषि मूल्य आयोग में किसानों के प्रतिनिधि शामिल किये जायें भले ही उसमें उपभोक्ताओं के भी प्रतिनिधि क्यों न शामिल हों। जब तक किसानों के प्रतिनिधि कृषि मूल्य आयोग, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के सदस्य नहीं होंगे, तब तक खेती की पैदावार को संतुलित दाम नहीं मिल सकेगा गन्ना, जूट, कपास, आलू, प्याज, गेहूं, चावल से सम्बन्धित सभी मिलों एवं कारखानों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तभी हम समाजवादी समाज के निर्माण के सपने को साकार कर सकेंगे।

खेती को उद्योग माना जाए, खेत पर काम करने वाले किसान एवं खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार एक आयोग कागठन करे जो कारखानों

में बनने वाली वस्तुओं और खेती में पैदा होने वाली वस्तुओं के लागत खर्च एवं न्यूनतम दाम निर्धारित करने की सिफारिश करे ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, सबसे बड़ा तर्क आज दिया जा रहा है कि किसान जो है वह कुलक है। मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान में 90 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो 10 एकड़ से कम खेत जोतते हैं और समाजवादी जो धन धरती के बंटवारे की बात तो करते हैं, कम खेत जोते वाले गरीब तो कई लाख किसान होंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि जब देश में 10 एकड़, 8 एकड़, 6 एकड़, 3 एकड़, 2 एकड़ या 1 एकड़ के खेत वाले 90 प्रतिशत किसान हैं तो ऐसी स्थिति में माडर्न टेक्नालेजी का इस्तेमाल कैसे देश के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? आज हम ग्राउण्ड वाटर को भी नहीं दे सकते हैं । हम धरती के पेट में छिपे हुए पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते । जब तक हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते । मेरा आपसे निवेदन है कि आप देश के किसानों के संबंध में एक नीति बनाएं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि आज तपेदिक की सुई कारखाने में दो आने की बनती है लेकिन जब वह बाजार में बिकने के लिये आती है तो दो रुपये उसकी कीमत हो जाती है । जब सरकार टी०बी० के फेफड़ों पर भी इस तरह से टैक्स लगाएगी तो मैं नहीं समझता कि देश की हालत में सुधार आएगा ।

आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें लिखा है कि उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पै ने अपने भाषण में कहा है कि जब तक हिन्दुस्तान के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दाम निर्धारित नहीं किये जाएंगे तब तक किसानों को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता, तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा। जब तक किसान में खरीदने की क्षमता पैदा नहीं होगी तब तक उसमें भी सुधार नहीं आ सकेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान की तरक्की की तरक्की कृषि पर निर्भर है।

क्या कारण है कि आज गांवों से लाखों लोग, करोड़ों लोग शहरों की तरफ तेजी से भाग कर आ रहे हैं। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में 27 करोड़ मजदूर हैं, जिनकी तीन-चार आने रोज की आमदनी है । मैं पूछना चाहता हूं कि गांवों में जो किसान खेती करता है और उसके खेत में मजदूर भी काम करते हैं तो जब वह, घर में जो गल्ला होता है उसी गल्ले में से अपने मजदूर को पारिश्रमिक देता है तो वह कैसे खुशहाल हो सकेगा। ऐसे ही कितने ही किसान हैं जिनके पास एक एकड़, 6 बीधा, 4 बीधा से ज्यादा के खेत नहीं है । मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में 99 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से ऊपर के खेत नहीं हैं । एक प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे नहीं हैं जिनके पास इससे ज्यादा का खेत हो । आज किसानी करने वाले लोग गांवों में इतने परेशान और तबाह हैं कि जब हम गांवों में जाते हैं तो किसान हमसे कहते हैं कि इन्दिरा जी को हमारी हालत के बारे में बताइये । मैं इस बात को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों में 80-85 रुपये क्विंटल गेहूं बिक रहा है और उन गेहूं को खरीदने वाला कोई नहीं है । इससे किसान अपनी लड़की की शादी भी नहीं कर सकता; क्योंकि गेहूं को खरीदने वाला कोई नहीं है । जो मजदूर गांवों में रहता है और जो किसान पर निर्भर रहता है वह गल्ले को बेच कर बड़ी मुश्किल से अपने जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीद पाता है । उसी गल्ले को बेच कर अपने लड़के की फीस जमा कराता है । गल्ला बेच कर सीमेन्ट खरीदता है, गल्ला बेच कर अपने गांवों में जितने भी जीवन के रोजमर्रा के काम हैं वह करता है । जब किसान का गल्ला नहीं बिक रहा है तो मैं नहीं समझता कि कैसे वह अपनी पैदावार बढ़ा सकेगा । जब किसान की हालत खराब है तो मजदूर की जिन्दगी जो कि उसके ऊपर निर्भर रहता है, कैसे चलेगी ? किसान और मजदूर की जिन्दगी कम्पलीमैन्टरी और सप्लीमैन्टरी जिन्दगी है ।

जो लोग तर्क यह देते हैं कि किसानों की हालत सुधर रही है, खेती की पैदावार बढ़ रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को खेती का ज्ञान नहीं है, उनको हिन्दुस्तान का ज्ञान नहीं है । 'टाइम्स आफ इंडिया' में रिपोर्ट आई है कि हिन्दुस्तान के गांवों ने 60 सौ करोड़ रुपये का कर्जा देना है । आदरणीय उपसभापति महोदय,

[श्री कल्प नाथ]

अभी प्रधान मंत्रीजी के 20-सूत्री कार्यक्रम के कारण हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को कर्ज से मुक्ति मिली है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अब उनको कर्ज मिलेगा कहां से ? जो लोग छोटे-छोटे किसान हैं, मजदूर हैं वे किसी साहूकार से, सेठ से कर्ज मांगते हैं, तो वह देने को तैयार नहीं है; क्योंकि कानून ऐसा बन गया है कि अगर वह कर्ज देगा तो उसे वापस मिलेगा नहीं। इसलिये सेठ, साहूकार ने कर्ज देना बंद कर दिया । आजकल मजदूरों को, किसानों को अपनी जिन्दगी की रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिये कर्ज की आवश्यकता होती है और वह कर्ज उसे मिल नहीं पाता । इसलिये इस समस्या को हल करने के लिये आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिये हिन्दुस्तान में 50 हजार ग्रामीण बैंक खोले जाने चाहियें । 7 लाख गांवों में 50 हजार ग्रामीण, रूरल बैंक्स खुलेंगे तब आप हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता को ऋण से राहत दिला सकेंगे ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, हम चाहते हैं कि अण्णा साहेब शिन्दे, जो किसान परिवार के लड़के हैं वह गांवों में जा कर रहें और गांवों में रह कर किसानों की हालत को देखें । आज हिन्दुस्तान का किसान और मजदूर श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना नेता मानता है और वे इस देश की सर्वमान्य नेता बन चुकी हैं । चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सभी उनको अपना नेता मानते हैं । लेकिन हमारे देश में गरीब किसान की स्थिति सुधारने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए अब तक जो कदम उठाये गये हैं उनसे उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हमारे देश की खेती और किसानों की ओर ध्यान दिया जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग अर्थात् एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को ओवरहाल किया जाये, इसको रिआर्गेनाइज किया जाये । मैं चाहता हूं कि इस आयोग में चौधरी रणबीर सिंह, श्री अण्णासाहेब शिन्दे और श्री हर्ष देव मालवीय जैसे किसानों के बेटों को रखा जाये जो यह कहा जाता है कि कंज्यूमर के प्रतिनिधि भी उसमें हों, उनको भी उसमें रखा जाये । जब हम इस प्रकार से अपनी नीति अपनाएंगे तो हमारे देश में एक नये समाज की रचना होगी और भारत दुनिया के अन्दर अन्न का भंडार बन सकेगा ।

धन्यवाद ।

SHRI N. G. GORAY: Sir, what we are doing today is, we are discussing the obvious because so far as the crucial role of agriculture in the Indian economy is concerned, it was never in any doubt. Everybody agrees that agriculture is the most crucial sector of our economy. Even so, I would like to congratulate my friend, Mr. Gulabrao Patil, for having brought this question before the House. And I would like to congratulate all the speakers who have participated in the debate because this is one subject, Sir, which, as you must have seen, has cut across all party affiliations and loyalties. The surprise is all the more, therefore, that when all the parties are united and almost unanimous on this particular issue, why it is that almost every time we have to raise it in this House.

Sir, as I said, this is obvious because out of our total national income, more than 42 per cent is contributed by agriculture. And the second contribution comes from manufacturing industries, electricity, fertilisers and construction. Their contribution is only 23 per cent. While agriculture is contributing 42 per cent, the next contribution is 23 per cent. It is a wide gap. So, by and large, our nation's economy depends on agriculture. If that is so, and if it is also true that all the parties are agreed that that is the sector which is most neglected, then why is it that the Government has been so far negligent about the various issues that face our agricultural sector? Sir, it is common knowledge that so far as industrial workers are concerned, they came late on the scene. It was only after the industrialisation of this country started that the so-called proletariat came on the scene, round about 1870 or 1880. But after only 90 years, due to the organisation, due to the

leadership, now it can be said that they are not a neglected community. I know that there are many outstanding questions so far as Indian labour is concerned. But you cannot say now that it is an exploited section. You cannot say that it is an unorganised section. You cannot say that it is a sector which has been neglected. But in spite of the fact that the agriculturist has been with us for the last so many centuries, and most probably he is going to continue to be with us for the next few centuries, how is it that we have not been able to find a solution to one of the most crucial problems facing the agriculturists?

Why is it that he is exposed to all the vagaries of the market, in spite of the fact that we have been an independent country for the last twenty-five years? The day before yesterday when I spoke on the budget, I tried to bring to the notice of the Government the imbalance that exists between the urban areas and the rural areas. And, Sir, I was a little sorry when Subramaniamji made a pointed reference to my speech, but did not take adequate notice of what I had said. What I wanted to say was that our entire budget—not particularly this year's budget, but budget after budget—has been urban oriented. I am not saying that it is a rightist budget or leftist budget. It is an urban oriented budget, unmistakably. I want the budget—at least the budget of India—to be rural oriented. Sir, I was a Marxist at one time and am still a socialist. But socialism has not been able to solve this question. If my friend Shri Bhupesh Gupta had been there, he would have to admit that. Somehow Communist countries have failed to solve this problem of agriculture. It is not surprising that even today Soviet Russia has to import from America. That is not to say that everything in America is all right. If you say that there is something wrong with Russia, then immediately it will be said that you are in the American lobby. That is the whole trouble. When I went to Poland, the Polish Communist Party Chief said : "We are not going to have collectivisation because it does not suit us". He said: "China may have collectivisation; Russia may have collectivisation. But in Poland we are not going to have it because it is not accepted by our peasants" after all agricultural produce is one of the important sectors of our economy. So, Sir, we in India should be the first to show to the world that in a developing economy the agricultural sector is getting its dues. That is my plea. I tried to convince or tried to persuade the Government to agree to this that our budget ought to have been rural oriented. And that is what brings us to this question of prices. After all, agricultural produce is a commodity like any other commodity. If in the industrial sector the prices of commodities begin to slide down, immediately there is a hue and cry. If the prices go down, the industries immediately cut down the production. This is some thing which is not possible so far as agricultural sector is concerned because agriculturists have nothing else to fall back upon. He must produce and he goes on producing because unless he sells his goods in the market, he just cannot live. And that is the biggest difference between the industrial labour and agricultural labour. If the industrial labour is dissatisfied, they will go on strike. If the capital is suffering, it will go shy. Why? Because there is no investment. Today you find that the industrial sector is sluggish. Why? Because nobody is there to invest. Why? Because the rates of interest are high. Immediately there is a reaction. So far as agricultural sector is concerned, there is no reaction at all. If it produces more, the irony is this. I want Shri Shinde to consider this. As soon as there is a bumper crop, instead of gaining from it, the agriculturists start suffering. That is the irony. It is not only in cotton; but it is also in potato. Last year there was a bumper crop in potatoes and I was told that in U.P. they had to sell potato at Rs. 25 per quintal.

3 P.M.

And, Sir, because they could not make both ends meet, some of the agriculturists allowed their potato to remain in the soil;

[Shri N. G. Goray.]

and they never took it out. Yesterday, Mr. Shinde, I suppose, said that potato production this year is going to be of the order of six million tonnes. It is good and it is indeed very good. He also pleaded that it should be considered to be part of food. But the fact remains that as soon as there is more of potato, the prices come down and they come down so heavily that it is almost a collapse. Prices collapse. That is what is happening so far as wheat is concerned and that is what is happening so far as rice is concerned. Everybody here who comes from the rural areas and who has not taken any dogmatic stand, will agree that the prices of wheat and rice have slumped far below the support price. Now, is the Government in a position—I would like to ask Mr. Shinde a simple question—to say or to give a promise to the peasant that whatever produce he has, whether it is rice or wheat or barley, the Government will purchase every grain of it at the support price or at the price recommended by the Agricultural Prices Commission? I think that is not the position the Government is ready to take because the Government has said that so far as wheat is concerned, the procurement target is fixed at 5.5 million tonnes and beyond that, Sir, it is not able to go. It is because the Government has not perhaps the required finance and the Government has not enough storage capacity. So, as soon as the bumper crop is there, the agriculturist has to face the slump and that is what is happening. Sir, I think he must have received a copy of the memorandum submitted by the Rajasthan Kisan Sangh and in one of the paragraphs they have said like this:

> "Without any alternative left to us, when we are being forced to sell our produce at Rs. 60 or Rs. 55 per quintal of paddy, and at Rs. 80 to Rs. 90 per quintal of wheat, causing a great loss to us, our hearts begin to weep to see that charcoal is sold at Rs. 75 a quintal and oil-cake at Rs. 115 to Rs. 120 a quintal."

So, it is much better to burn down the trees and turn them into charcoal and sell it at Rs. 75 per quintal than to produce wheat or paddy and sell it at Rs. 50 or Rs. 70 a quintal. This is the crux of the problem. Therefore, if the prices of these commodities slump, what will happen? It will give a very big jolt to your economy in the sense that you will see that your own market is shrinking. After all, what is to day the irony of the situation? The irony of the situation is that you are producing more steel, but nobody is buying; you are producing more cement, but nobody is buying it; you are producing more textiles and there is nobody to buy; and you are producing more plastic goods and there is nobody to buy them. Now, this is the sort of contradiction that is there between what you are producing and what the consumer is capable of consuming. But, how do you solve it? Why does it take place? It takes place because there is no purchasing power. Unless you inject that purchasing power into the system by making it possible for the kisans and the landless labourers who constitute the majority of the population, you will find while you are producing more, there is no market at all. And, you are not going to export plastic goods; you are not going to export your cement; and you are not going to export much of your steel. So, what I am pleading for is that you must, from your own point of view, have your home market in your hands and if the home market shrinks, then, it will be a very difficult situation for the economy of the country as a whole.

Now, Sir, apart from the economic effect of this collapse of prices, I would like to point out to you the social effect also. My friend there who just now spoke, Mr. Kalp Nath, stated that because of the increasing impoverishment of the villagers, thousands of people are racing to the cities, creating slums, creating pollution, creating problems of hygiene, etc. Now, what do you do to fix them up in the villages? If they find that the economy in the village is ruined, then what can they do? They have to migrate to the cities and make the problem difficult. But it is not only that. I would like to warn all of you. You are talking of the twenty-point programme, ceiling on land and distribution of land. But I may tell you of

my own experience. It is not enough to distribute the land. Yesterday, Mr. Pranab Mukherjee, the Minister of State in the Ministry of Finance, when he was asked how much loan has been provided by the nationalised banks, he gave the figure which came to this that four lakh people have been distributed about Rs. 16 crores, which comes to Rs. 400 *per capita*. Now, Rs. 400 is not enough to buy a single bullock. You see you cannot buy even a single bullock. Just now, one of my friends here stated that a pair of bullocks will cost Rs. 3000. So it is not enough to take away the land from a 'kulak' or a rich peasant and give it to landless peasants. You must provide him with sufficient where-withal to buy bullocks, to buy fertilisers, to have electricity, etc. etc....(*Time bell rings*). Otherwise, what is happening is that the land is coming back again to the rich peasants.

What has happened in Maharashtra? You distribute the land to the landless, but because the man has not the means of cultivating the land there, it comes back to the "Marwari" or to the rich peasant...(*Interruptions*). And he alone is in a position to utilize it. So, on the one hand, you may be fulfilling the twenty-point programme, on the other hand you will find that the whole thing is being re-cycled, again coming to the rich peasant. Now, you do not want this. But this is what is happening, and the cities are getting richer, richer and richer, while the villages are getting poorer, poorer and poorer. Go to Bombay, go to Calcutta or come to Delhi. See the palatial buildings that are being built here—high rise; this is the new word used now. The peasant's house is collapsing and there is not enough money to re-build it. This is what is happening.

I would, therefore, like to point out to you that it is not a question of peasant lobby against the industrial lobby. It is not a question of being right or left. It is a question of just boosting India's economy. And unless this imbalance is corrected and our whole economy is reoriented in such a fashion that the agriculturist who constitutes about 80 per cent of your population, has the legs to stand on, he will suffer—not only suffer economically but he will become a slave of the city-dweller.....(*Time bell rings*). In spite of your abolition of the bonded labour—after all, what is 'bonded labour'? It is only a phrase—he may not be a bonded labourer, but the man has to slave at three rupees per day or four rupees per day, even though you have stated that the wages will not be less than five rupees per day. But who is going to pay him rupees five? You look at the whole question in the total complex. I would beg of Mr. Shinde to take some steps. Why should there be such a difference between what an agriculturist wants and what the APC is recommending? There must be some *via media*. Why is it that the A.P.C. does not sit with Members of Parliament and tell them how it arrives at this figure and tell them how it is economical for the peasant to grow foodgrains even at this rate? We would like to know this. And this can be done. In spite of the fact that there is no peasant lobby, the peasant will have to be saved, because unless agriculture is safe, India's economy cannot survive.

श्री हरिसिंह मगुबावा महीदा (गुजरात): उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री गुलाबराव जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं श्री पाटिल जी को कि सही वक्त पर सही सवाल इस सभागृह के समक्ष उन्होंने उपस्थित किया।

मुझे ज्ञात है, बजट में सरकार ने कृषि विकास के लिए जो कदम उठाये हैं उन योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को ही दी गई है। बिजली, सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि के लिए समुचित धन की व्यवस्था की गई है और इस सब से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा। मेरा भी यह विश्वास है कि कल ही हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सभागृह में कहा था कि हम एग्रीकल्चर को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या सही है कि देश की समस्याओं

[श्री हरिसिंह भगुबावा महीदा]

का हल कृषि के विकास से ही होना सम्भव है। कृषि का विकास होता है, लेकिन कृषक का क्या हाल है ? यह सवाल आज सभागृह में गुलाबराव जी ने पैदा किया। कृषि का विकास होता रहता है, अनाज का उत्पादन बढ़ता है, बिजली का उत्पादन बढ़ता है। हमने कई योजनायें बनाई जिनकी वजह से खेती का विकास होता रहता है। लेकिन 1972 से लेकर आज तक जो हालत किसानों की हुई है, जो बरबादी किसानों की हुई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारा लक्ष्य इस तरफ नहीं जाएगा तो देश के अर्थतंत्र पर भारी खराब असर होने के सिवाय नहीं रहेगा।

जब जब सभागृह में या बाहर किसानों का सवाल उपस्थित होता है तो इस सवाल को कुछ लोग कुलक का सवाल, जमींदारों का सवाल कहकर उसका महत्व कम किया करते हैं। आज जो सवाल पैदा हुआ है, मेरी दृष्टि से वह कोई दो चार प्रतिशत जमींदारों का सवाल नहीं है जिनकी जोत 50 एकड़ से ज्यादा है। यह बड़े काश्तकार और बड़े किसान का सवाल नहीं है। 90 परसेंट से ज्यादा जो खुद खेती करते हैं, खून-पसीना बहाते हैं देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति लगाते हैं इनका सवाल महत्व का सवाल है। कल माननीय कृषि मंत्री श्री शिन्दे ने भी बताया था कि बारले ग्राम, की स्पोर्ट प्राइस गेहूं की तरह गवर्नमेंट ने नियत की है। सवाल स्पोर्ट प्राइस की नक्की करने का नहीं है। यह जो प्राण प्रश्न पैदा हो गया है, बर्निंग प्रोब्लम किसानों के लिये पैदा हो गई है वह प्रोब्लम सिर्फ गेहूं की, बारले की स्पोर्ट प्राइस नक्की करने से हल होने वाली नहीं है।

जो हमारी डिप्टी फाइनैंस मिनिस्टर श्रीमती रोहतगी हैं उन्होंने कल लोक सभा में गुजरात क बजट पर चल रही बहस का उत्तर देते समय विश्वास दिलाया कि गुजरात में जो प्राइस गिरने लगी हैं उसे और ज्यादा नहीं गिरने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारी आजकल हालत क्या है ? किसान खेती में उत्पादन में बढ़ाने के लिये जिन चीजों को इस्तेमाल करता है उन सब चीजों के भाव आज क्या हैं ? और खेत पैदावार का भाव क्या है ? मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं।

'72 में यूरिया के भाव 50 किलो के 48 रुपये थे और '75 में उसके भाव 94.30 रुपये हो गये। डी०ए०पी० के भाव 1972 में 63 थे वह बढ़ कर 1975 में 145 रुपये हो गये। अमोनियम सल्फेट के 1972 में भाव 26 रुपये थे थे जो '75 में बढ़ कर 48 हो गये। सुपर फास्फेट के भाव जो '72 में 20 रुपये थे वह बढ़ कर 42 हो गये। पोटाश के '72 में 29 रुपये थे जो '75 में 52 रुपये हो गये। क्रूड के एक बैरल के '72 में 95 रुपये भाव थे जो कि '75 में 235 हो गये। आयल के एक बैरल के '72 में 300 रुपये थे जो '75 में बढ़ कर 1560 हो गये। प्लांट प्रोटैक्शन के लिये पैस्टीसाइड्स सेवीन 10 परसैन्ट वाली जो एक थैली होती है जिसका वजन 25 किलो होता है '72 में उसके भाव 85 रुपये थे और '75 में बढ़ कर 160 रुपये हो गये। एक लीटर के नवाकरोन की कीमत '72 में 84 रुपये थी लेकिन '75 में 162 रुपये हो गई। डैमेक्रोन एक लीटर का जो '72 में 96 रुपये में बिकता था वह '75 में 167 रुपये में बिका है। डी०डी०टी० '72 में 12 रुपये के हिसाब से बिका है जब कि '75 में 22 रुपये के हिसाब से बिका है। बी०एच०सी० '72 में 6 रुपये पर पेकेट के हिसाब से बिका है जब कि '75 में 14 रुपये, पर पैकेट के हिसाब से बिका। '72 में मजदूर को 2.50 रुपये देने पड़ते थे, जब कि '75 में साढ़े पांच रुपये दिये गये।

इन सब के सामने जब खेती के पैदावार के मूल्य से कम्पेयर करते हैं तो आप अंदाजा लगाइये कि जो उसकी पैदावार होगी, जो उसकी उपज होगी, उसकी क्या हालत होगी। मूंगफली '72 में 20 किलो 40 रुपये में बिकती थी वह '75 में 62 से 65 हो गई और '76 में उसके भाव घट कर 28 से 31 तक हो गये।

मिलेट बाजरा '72 में 20 रुपये के हिसाब से बिकता था, '75 में 42 से 45 तक के बीच बिका जब कि '76 में उसका भाव 18 से 22 हो गया। गेहूं 20 किलो 18 से 22 रुपये मिलता था आज भी उसका यही भाव है।

कपास की हालत यह है कि वह '72 में 20 रुपये बिकता था और '75 में 35 से 40 बिका जब कि अब 18 से 22 हो गया है। सी० जे० '72 में 45 बिका, '75 में 55 और अब उसके दाम 45 से 50 हो गये हैं। कपास शंकर-4 जो '72 में 60 रुपये के हिसाब से बिका और '75 में 80 के हिसाब से बिका अब वह गिर कर 70 के हिसाब से बिका रहा है। ज्वार जिसके भाव '72 में 25 रुपये थे, '75 में 45 हो गये थे उसी की आज 15 से 20 रुपये के हिसाब से भी कोई खरीदने वाला नहीं है।

आज जो सवाल हमारे सामने है कि हम रेम्युनिरेटिव प्राइस नक्की करें, स्पोर्ट प्राइस नक्की करें, इससे हल निकलने वाला नहीं है। 1972 में जो चीजें पैदा करने के लिये इस्तेमाल होती थीं उन के भाव अब क्या हैं इस चीज को देखना है। 1972 में 15 हजार, 16 हजार का ट्रैक्टर मिलता था जो कि आजकल 36 हजार में भी नहीं मिलता है। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल आने वाली चीजें जैसे जैसे बीज हैं, बिजली है, फर्टीलाइजर है, इनके दामों में भी काफी फर्क आ गया है। किसान को अपने खेत के लिए पानी मिलता है या नहीं, इस बात को देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। अगर हमारे देश के किसान को खेत में अनाज उपजाने के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगी और फिर उसके अनाज का ठीक मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान की खेती बरबाद हो जाएगी और इसका दुष्प्रभाव हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इसलिए श्री गुलाबराव पाटिल जी ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह ठीक है कि सरकार खेत में पैदा होने वाली हर चीज के रेम्युनरेटिव प्राइस घोषित करे। आज हमारे देश का किसान पानी की दिक्कत का शिकार है और कुदरत की अनियमितताएं भी उसको परेशान करती हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि किसान को सिंचाई की फेसिलिटीज प्रदान की जायें। हमारी सरकार को चाहिए कि किसानों को सुविधाएं देने के संबंध में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करे। आज हमारे देश में हालत यह है कि हमारी सरकार की तरफ से ये बातें तो की जाती हैं लेकिन फिर भी किसान की हालत में सुधार नहीं होता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है? जब खेती का सेशन आता है और खेत से माल बाहर निकलता है तो किसानों की पैदावार को कोई खरीदने वाला नहीं होता है। इसके कारण भाव गिर जाते हैं। इसके बाद किसान बनिये के पास जाता है और बनिये का गुलाम बना रहता है। गुजरात के अन्दर पिछले वर्ष हमने देखा और इस साल भी देखा है कि किसान के पास पैसा नहीं होता है और मजबूर होकर उसको बनिये के पास जाना पड़ता है। बनिये उसके खून का पानी बनाने के लिए तैयार रहता है और उसका खून चूसता है। हमारे एफ०सी०आई० और अन्य संस्थाएं उसका माल खरीद नहीं पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे देश में जो छोटे-छोटे और मारजिनल किसान हैं उनकी हालत बड़ी खराब हो गई है। हमारे देश में इस प्रकार से किसानों का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। चौबीसों घंटे उनका एक्सप्लोइटेशन होता है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने इस दिशा में कभी सोचा है या नहीं? आज कहा जाता है कि हमारे देश में मंहगाई कम हो रही है। सारे देश में चीजों के दाम गिर रहे हैं। हमारे देश में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के गतिशील नेतृत्व में महंगाई का चक्र कम हो गया है और देश में अनुशासन का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि मंहगाई के दुष्चक्र का सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश के किसान पर पड़ा है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के वर्तमान नेतृत्व में बहुत बड़ी ताकत है। उसके दिल में हमारे देश के किसानों के लिए बहुत ऊंचा स्थान है और उनके लिए मां की ममता जैसा प्रेम है। इसलिए विश्वास है कि सबसे पहले किसानों की हालत सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। अगर हमारे देश के किसान की हालत में सुधार नहीं होगा तो हमारे देश में अन्न का उत्पादन भी नहीं बढ़ पाएगा।

हमारी सरकार ने मोटर कारों के भावों में कमी कर दी है, रेफ्रीजीरेटरों के भावों में कमी

[श्री हरिसिंह भगुबावा महीदा]

कर दी है और पंखों के भावों में भी कमी कर दी है, लेकिन जिन चीजों को किसान इस्तेमाल करता है, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनके भावों में कोई कमी नहीं हुई है। ट्रेक्टर के भाव में कोई कमी नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि अन्य सब चीजों की ओर हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान गया, लेकिन किसान जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया। कैसे हो गया, यह मैं नहीं जानता। यह सारा बजट देखिये। हमें जिस चीज की जरूरत होती है, बाजार से खरीदनी पड़ती है, उन सारी की सारी चीजों के भाव बढ़ते जा रहें हैं और खेतों में जो पैदा होता है, उसकी सब चीजों के भाव गिरते जा रहें हैं। तो आगे चलकर क्या परिस्थिति होगी, इसे देखकर हम चिन्तित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मान्यवर मंत्री जी, श्री शिंदे जी भी चिंतित होंगे और हैं। लेकिन सिर्फ चिन्ता से सवाल हल नहीं होने का। इसके लिये क्या कदम उठाये जाने चाहिएं: वे कदम कौन से हैं, यह देखने की हमें इंतजारी है और ये कदम कब उठाये जाने वाले हैं ?

मैं श्री गुलाबराव जी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया है, जिसकी इन्तजार देश के सारे किसान कर रहे थे, सदन के किसी भी कोने से इसका विरोध नहीं आया। शिंदे जी भी इसका विरोध नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मुझे यह भी विश्वास है कि आज सभागृह में इस ओर कुछ ठोस कदम उठाने का विश्वास दिलायेंगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्याज गुजरात में पिछले तीन महीने तक 40 रुपये का 20 किलो बिकता था। अब 5 रुपये मन यानी 2½ रुपये का 20 किलो लेने वाला कोई नहीं है। यह सवाल शिंदे साहब के पास आया है। यह सवाल कैसे हल होगा ?

Is there any protection to the farmers ? Will it be given any time? If it will be given, in what form will it be given? It may be declared today, we hope. I hope our desire should be fulfilled.

इंदिरा जी के नेतृत्व के नीचे जो हमारे मान्य कृषि मंत्री जी काम कर रहे हैं वे ऐसे सवालों को हल करने की कोशिश करें और आशा है कि वे ऐसे सवालों का हल ढूंढ़ने में ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति खर्च करेंगे।

इस आशा और विश्वास के साथ मैं श्री गुलाबराव के प्रस्ताव को समर्थन देता हूं।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, as it has been said by everybody, agriculture forms the backbone of our country and agricultural economy is definitely the backbone of the nation. The strength of the agricultural economy is the strength of the national economy. As far as agricultural sector is concerned, even after independence, it has continued to be neglected and that has been said by everybody. If we go to a village, we will find the real state of affairs that is going on in a village area. There are two types of cultivators. One is a cultivator who goes to the soil, is the real tiller of the soil. Another is the absentee cultivator. By absentee cultivator, I mean a cultivator who cultivates the land through hired labourers. For example, he may be a cultivator but he may be having a side business also. A lawyer, a doctor or any person who has got some other business, may also take to cultivation...

SHRI N. G. GORAY: And Parliament Members.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Of course, membership of Parliament I do not consider it as career. What I submit now is that some person may take to cultivation as a side business. But, a lawyer should stick to his own legal profession; a doctor should stick to his medical profession; a businessman should stick to his profession. What happens today is, if a man has got money, he can purchase the land and through hired labourers, becomes a cultivator. He is in a better position also because he can go to a bank, get loans because credit facilities are there for him.

From his business also, from the legal profession or from the medical profession, he earns and puts that money into the land. But what about the other cultivators? I am speaking of the cultivator who gets up early morning at 5 A.M., goes to his paddy fields with his two bullocks, ploughs for the full day. I am speaking of that cultivator. He toils day and night in the paddy field. What is his position today? What is his purchasing power? As far as his purchasing power is concerned, it has been explained by Mr. Goray today as well as during the discussion on the Budget. I need not go into that matter. But what is the extent of credit facilities being provided to the farmers? The hon. Finance Minister, Shri C. Subramaniam, himself admits that there is a big gap between the availability of funds and the actual requirements of the farmers. Therefore, is it not the duty of the Government and the Finance Ministry to find out the resources and help these poor farmers? Let us take the statistics published in regard to the loans advanced to the farmers by the nationalised banks and other institutions. Who are the persons who have been benefited by such loans? What about the poor cultivator who depends only on his two bullocks for ploughing the paddy field? Does he get the requisite help from the nationalised banks or the co-operative societies of the regional rural banks? I am not referring to the major cultivators. They are in a position to get credit facilities. But a large section of the farmers does not get the credit facilities. Of course, in my own State, Kerala, the agriculturists who pay the Agricultural Income-tax may get loans from banks and so on. But 90 per cent of the cultivators do not come under the category of assessees. What about their position? Their position is miserable even today. They are not able to get even Rs. 500, not to speak of Rs. 3,000 or Rs. 4,000, to purchase bullocks and so on. They are not able to get loans from the Syndicate Bank, the Canara Bank or any other bank. I have spoken to some of the bank managers. They say 'We will have to see his repaying capacity; he should be in a position to return the amount lent to him'. They make sure about his repaying capacity and then only they advance him the loan.

Then, about crop insurance. No decision has been taken in this regard. The farmer should be in a position to go to the village panchayat office and insure his crop. This would instil a feeling of security in the minds of the farmers. How can we depend only on nature? Our crops are destroyed by pests, floods and so on. Much has been said about this scheme. But nothing has been done. I submit that this scheme should be formulated as early as possible.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another important matter. This is in regard to the use of the underground water resources. There is enough quantity of underground water But this has not been made use of. This should be tapped and made use of. It i not possible for the farmers to do it. Bu what schemes have been worked out t tap the underground water resources Nothing has been done in this regard. saw a report that they are going to estab lish a Board for this purpose in Keral Such Boards should be established througl out India. There should be a machiner to enable the farmers to make use of tl underground water resources.

Another thing is in regard to the fra mentation of lands in villages. The should be a national economic holding f every cultivator. The maximum ceili has been fixed, 15—20 acres or whatever may be. Similarly, minimum holdir should be fixed for all the crops. Eve farmer should possess the prescribed mi mum holding so that he would be a to produce the maximum. But no eco mic holding has been fixed in any St Every farmer should possess at least 1 acres of paddy field for maximum p duction from his land. That has not b worked out and the experts have not

[Shri Hamid Ali Schamnad.]

anything about it. Therefore, what I submit is that on a national basis economic holdings should be fixed for each crop. This is absolutely necessary for maximising production by cultivators.

Sir, with regard to fall of prices everybody was talking and I do not want to repeat. But that is a matter of fact which has to be considered. Today I have seen in the papers that the Karnataka Government is going to purchase all the agricultural production but whether it is possible and whether it will materialise I do not know. If that could be done then it will be a nice thing and I wish every State does it so that support prices, especially for food crops like paddy and wheat, could be given to the cultivator who produces them in order that he can clear his debts, look after his bullocks—which is more important—and is able to make both ends meet. This is absolutely necessary.

Another thing is, as far as the rural sector is concerned, now you have given some importance to the rural people.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Were we not giving before?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: May be. But I am saying, by and large. A few people here are in high positions. But what I say is, the farmer's children should also come up in life. They should also become advocates of the Supreme Court, they should also become doctors, technicians and so on and should come up in every walk of life. The farmer should be able to make use of his children in the best interests of the nation as a whole. It should not be that a farmer's son should in turn become only a farmer again. Normally what happens is, when a farmer is dead, what he would have left behind him is only the debt that he had incurred and his son will have to struggle with it. Therefore, instead of such a thing happening, a standard should be given to the farmer. What I suggest in this connection is that there should be some proper planning for one career for one person and I would like to know whether such a thing cannot be worked out.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : If they all become doctors and engineers, then who will do farming ?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : I would like to know whether it can be worked out. Sir, the Karnataka Government was thinking in those terms because a doctor's son can become a lawyer or a lawyer's son can become a doctor and so on. Why cannot a farmer's son take up the medical profession or the legal profession so that he is given the dignity of the profession ? Today a doctor is given better respect in the society than a cultivator. A cultivator who owns three, four or five acres of land should be given equal status in life just as in the case of other professions.

With these words, Sir, I congratulate the hon. mover of the Resolution and thank you for having given me this opportunity of speaking.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, सारे सदन ने श्री गुलाबराय पाटिल जी के प्रस्ताव का स्वागत किया है और सारे सदन ने उसको समर्थन दिया है। यह एक बहुत ही माकूल बात है। यदि हम अपने देश के इतिहास को देखें तो यह किसान भारत की रीढ़ है। हमारे हिन्दी के बहुत बड़े कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। उन्होंने गीत गाया है और बहुत सुन्दर गीत गाया है —"भारत माता ग्राम वासिनी"। भारत अपने ग्रामों में रहता है और पहले यहां दूध और घी की नदियां बहती थीं। मगर बाद में यह किसान बड़ा दुखी हुआ। अंग्रेजी शासन आने के बाद 1853 से लेकर 1900 तक के 47 सालों में हिन्दुस्तान में इतने अकाल पड़े कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दो करोड़ 80 लाख किसान दाने दाने को तरस गये और मर गये। अंग्रेजों ने लिखा है :

"The bones of Indian have bleached the plains of India."

तो बड़ा दुःखी हमारा किसान था और अगर अंग्रेज 2 करोड़ 80 लाख मानते हैं तो 5 करोड़ किसान तो मर ही गये होंगे। बड़ी गरीबी थी। जब गांधी जी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व लिया तब उन्होंने जो सब से बड़ी अपनी देन हिन्दुस्तान को दी 1921 में वह यह थी कि उन्होंने किसान को दरिद्र नारायण माना। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का मकसद क्या है ? हम गरीब किसानों को रोटी देना चाहते हैं। यह बड़ा गरीब है और उस जमाने की गरीबी को याद दिलाने के लिए और वह गरीबी आज भी पूरे तौर से दूर नहीं हुई है, मैं आपकी आज्ञा से दो, एक कविताएं सुनाऊंगा। यह किसानों की कविताएं हैं और बड़े दर्द की कविताएं हैं। हमारे अवध के प्रदेश की यह कविता है :

एक किसान के रोटी नाहीं, दालौ घीउ पोती नाहीं,
जिनके के लागे हैं अनेकों ठगहार।
हैं साम्राज्य स्वान राम देखो, बड़े बड़े मुंह बाये हैं।
पूंजीवाद बिलार बने है, पंजा खूब गड़ाये हैं।
तालुकेदार बने हैं बन्दर, दब के घात लगाये हैं।
गीध बने फिरते व्यापारी, सिर ऊपर मंडराये हैं।
वैद्य कहैं दुखिया किसान यह दशा देख घबराये हैं,
जिनके लागे हैं अनेकों ठगहार।

एक और कविता ब्रज भाषा में है। उसमें एक किसान ने गीत गाया कि :

जागौ वीर किसानौ नीति तुम अपनी पहिचानो—टेक,
चेत चेति अब जाओ सोबते बहुत दिना बीते,
घिसौ दिना और राति अंत में रीते के रीते,
न तन ढकने को है कपड़ा,
रक्त मांस गयौ सूखि, सूखि गयौ ऊपर को चमड़ा,
मौत ते लड़नो ही जानौ। जागो वीर।

जिन्दगी क्या है ? मौत से लड़ना है। देखिए, यह गरीबी हमारे देश में थी और हमारे देश में किसान का अपना महत्व है। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, बहुत से नाले हैं, तालाब हैं, मगर गंगाजी की पूजा होती है। गंगा जी की पूजा और उनका आदर इसलिए होता है कि लाखों करोड़ों किसान अपने पैर की धूल को गंगा जी को दे देते हैं। गंगा में जाकर वे स्नान करते हैं और गंगा को अपने पैर की धूल दे देते हैं तो उससे गंगा जी बड़ी हो जाती हैं। हमारे गांधीजी इतने बड़े हो गये, हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े हो गये, हमारी इंदिरा जी इतनी बड़ी हो गयीं क्योंकि जहां वह जाती हैं वहां लाखों किसान उनकी मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। यह किसान हमारे देश की महानता का मूल स्रोत हैं। किसी सज्जन ने कहा था और वह मानने की बात है कि स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत तरक्की की है। हमने जमींदारी प्रथा को खत्म किया, हमने तालुकेदारी प्रथा को खतम किया। जो मध्यस्थ प्रथा है 'उस को भी हमने बहुत कुछ खत्म किया, मगर उसके बाद भी किसान की गरीबी दूर नहीं हुई और आज के आंकड़े आप जानते हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता, देश के अंदर कुल 6 या 7 प्रतिशत किसान ऐसे हैं कि जिनके पास दस एकड़ से ज्यादा की आराजी है। 50 प्रतिशत काश्तकार हैं जिनकी आराजी 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम है और जो खेतिहर मजदूर हैं करोड़ों करोड़ उनकी तो हालात को क्या कहा जाय। इनको हमने जरूर मुक्ति दी जमींदारी शोषण से। मगर जो व्यापारी गिद्ध हैं, इनसे इनको अभी छूट नहीं मिली।

हमारे कल्पनाथ जी ने बताया आपको अपने भाषण में, उन्होंने गन्ने की बात कही। आपको मान्यवर, मालूम होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज गन्ने के जो कारखानों के मालिक हैं, मैं चाहता हूं कि शिन्दे जी इस तरफ ध्यान दें, वे 16 करोड़ रुपया किसानों का रोके हुए हैं। 16 करोड़ रुपया किसानों को नहीं दे रहे हैं। सरकार प्रयास करके हार गई और यह जो चीनी के बड़े बड़े मालिक हैं जो बड़ा मुनाफा कमाते हैं वे नहीं सुनते। गन्ने का दाम जहां पार साल 14 रुपये मन था, इस साल उन्होंने 12 रुपये मन कर दिया। किसानों के हाथ में क्या आया इससे हमको मतलब है। इस तरह करोड़ों रुपये इन्होंने पैदा किये और यही चीनी मिल मालिक समाज में गन्दगी के बड़े कारण हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अन्य प्रदेशों की राजनीति

[श्री हर्षदेव मालवीय]

में सबसे बड़ी गन्दगी के कारण यही बड़े-बड़े चीनी के मिल मालिक हैं और हम कुछ नहीं कर सके, क्षमा करें, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके।

एक बड़ी मजेदार बात है : अभी हमारे महीदा जी ने बताया कि प्याज से अंगूर सस्ता बिक गया । टके सेर भाजी, टके सेर खाजा अंगूर का दाम दिल्ली में आलू और प्याज से सस्ता हो गया । तो हमारी यह जो प्राइस पालिसी है, मूल्य नीति है, इसका एक उदाहरण है । बात साफ यह है कि हमने स्वतंत्रता के बाद बहुत कोशिश की । यह मैंने मान लिया अगर कोई कहे कि किसानों की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया । हो सकता है कि यह बजट कोई कह दें अरबन ओरियटेंड है । बात मानी जा सकती है । किसान की तरफ ध्यान तो गया मगर जितना ध्यान जाना चाहिए था वह नहीं गया । इसलिए कि जब तक किसान को आप उसके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य नहीं देंगे, जब तक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जो सामान कारखानों में बनता है, और किसान के उत्पादन में जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक एक तरफ तो चीजों का दाम बढ़ता जाएगा जैसे फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ा दिये आपने, और चीजों के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गल्ले का भाव गिरता जा रहा है । यह कहना कि थोड़े से कुलक हो गये, यह ठीक नहीं है । कुलक कितने हैं हिन्दुस्तान में ? कुलक के नाम से आप चाहे बदनाम करें, कुलक तो होंगे, जैसा मैंने कहा 4-5-6 परसेंट होंगे, 10-15 एकड़ वाले कितने हैं ? थोड़े से हैं जिनको ऊंगली पर गिन लीजिए । फिर उसके बाद सबसे अधिक आपके दो एकड़ या 1 एकड़ वाले काश्तकार हैं । । इनके लिए कल शिन्दे जी ने जो ऐलान किया उसका बड़ा स्वागत हुआ, आज अखबार में छपा है, हमने सुना और बड़ी सुन्दर बात होगी कि हम एक सपोर्ट प्राइस रखेंगे मगर एक बात जरा ध्यान में रखिये। जो किसान बेचारा 6 मन, 7 मन, 8 मन गल्ला लेकर बेचने जाता है तो ये जो आपके 105 के भाव पर खरीदने वाले हैं, ये तो कहीं रेगुलेटेड मार्केट में होंगे, बड़ी बड़ी मंडियों में होंगे। किसान तो बेचारा वहां पहुंचता ही नहीं है। उसी को जिसे अंग्रेजी में 'डिस्ट्रैस सेल' करना कहते है । क्योंकि किसान को दवा लानी होती है, मिट्टी का तेल लाना होता है और बहुत से काम करने होते हैं इसलिये वह पास की मंडी में जाकर 70 या 80 रुपये के हिसाब से गेहूं बेच आता है । वह अपना गेहूं आढ़तियों के द्वारा बेचता है । हमारी सरकार ने आढ़तिये को दबाने के लिये कदम उठाये हैं, लेकिन फिर भी आढ़तिये या उनके दलाल गांवों में जगह-जगह पर फैले हुए हैं । छोटे किसान जहां जा कर अपना गल्ला बेचते हैं वहां पर वे मौजूद रहते हैं । वे किसान से 80 रुपये के हिसाब से गेहूं खरीदते हैं और सरकार को 105 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं। सरकार उस गेहूं को आगे 125 रुपये के हिसाब से बेच देती है । जिस चीज के लिये किसान को 70-80 रुपये दिये गये वही चीज बाजार में 125 रुपये में बिकती है । यह बड़ा भारी अन्याय है और इस अन्याय को आपको रोकना होगा ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । वह यह कि देश की अर्थ नीति को, अर्थ व्यवस्था को थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से देखिए । संयुक्त राज्य अमेरिका, आप उसे साम्राज्यवादी देश कहिये या कुछ और लेकिन यह बात ठीक है कि वह एक ताकतवर देश है । वह एक शक्तिशाली देश है। क्यों ? आप संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास पढ़िये । वहां की जो आर्थिक स्थिति है उसका मूल कारण वहां की खेती है । वहां पर यूरोप से लोग पहुंचे । वह हमारे भारत से क्षेत्रफल में चार गुणा है । बड़े-बड़े खेत उन्होंने वहां बनाये हैं । वहां उन्होंने पशुपालन किया और खेती की । खेतों में जबर्दस्त उत्पादन हुआ । उसी खेती से वहां की समृद्धि है।

उद्योगों में जब कोई सामान पैदा होता है और पैदा हो करके अगर बाजार में पड़ा रहे तो कोई फायदा नहीं । उसका फायदा तभी है जब वह बाजार में आए और लोग उसे खरीदे । जो पैसा आए वह फिर प्रोडक्शन में लगे और प्रोडक्शन में जो चीज पैदा हो वह फिर बाजार में आए और फिर उसको खरीदा जाए । यह होता है स्पाइरल ग्रोथ । अगर किसान की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी।

आपकी सारी योजनाएं बेकार हो जाऐंगी । जब किसान की खरीद शक्ति बढ़ती है तो आपकी सारी योजनाएं भी ठीक तरह से चलने लगती हैं ।

आज आपने इंडस्ट्रीयल प्रौडक्शन किया और मान लीजिये 500 करोड़ रुपये का सामान बनाया और वह सारा का सारा सामान देहात में चला गया अगर किसान उस माल को साढ़े पांच सौ या छः सौ में खरीद लेता है तो वह पैसा आपके कारखाने में फिर आ जाता है और उस पैसे से आपके कारखाने में फिर सामान बनने लगेगा । इसे स्पाइरल ग्रोथ कहते हैं।

जिस चीज की सारे सदन में मांग हुई है उसको *शिन्दे जी ने माना है । आप जानते हैं वह स्वयं किसान* परिवार में पले हैं । वह जानते हैं कि जब तक किसान की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती है तब तक हमारा प्रौडक्शन नहीं बढ़ सकता है । सबको मालूम है कि छोटे-छोटे कारखाने बन्द पड़े हैं । इण्डस्ट्रियल स्टैगनेशन आने लगा है । उत्तर प्रदेश में 200-400 छोटे-छोटे कारखाने बन्द होने लगे हैं । अगर किसान की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती है, देहाती क्षेत्र में रुपया किसी तरह से नहीं आता है तो कारखाने बन्द होते रहेंगे । इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज प्रधान मंत्री का 20-सूत्री कार्यक्रम है । मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण आइटम है हमारे देश का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम । हमारे देश में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम तब तक ठीक प्रकार से नहीं चल सकता है जब तक कि हमारे देश में काफी अनाज की उगाही नहीं होगी । मैं माननीय शिन्दे जी से निवेदन करूंगा कि हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी मण्डियां हैं या जो हमारे देश में फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया है, वे सारे अनाज को नहीं खरीद सकते हैं । अगर जो अनाज आप खरीदते हैं उसकी तरफ ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की कुल पैदावार का 10 परसेन्ट अनाज ही आप खरीद पाते हैं । कहा जाता है कि हमारे देश में 115 मिलियन टन अनाज की पैदावार होने जा रही है, लेकिन आप केवल 10 मिलियन टन ही खरीद पाएंगे । कपास के लिए आपने कौटन कारपोरेशन आफ इण्डिया बनाया हुआ है । इस कारपोरेशन के अन्दर कितने घोटाले हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । पब्लिक अण्डर-टेकिंग कमेटी की जो रिपोर्ट हमने सदन में पेश की है, उसको अगर माननीय सदस्य पढ़ें तो उनको सही स्थिति की जानकारी हो जाएगी । वहां पर यह कहा गया कि कितनी ही कौटन जलकर भस्म हो गई । इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत कपास पैदा होती है, लेकिन कौटन कारपोरेशन सिर्फ 20 करोड़ रुपये का ही कौटन खरीद पाती है । किसानों की कपास खरीदने के लिए कौटन कारपोरेशन के पास पैसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को ठीक करना होगा और अधिक से अधिक मात्रा में प्रोक्योरमेन्ट करना पड़ेगा । आप बफर स्टाक भी बना सकते हैं । मैं तो चाहता हूं कि आप टोटल प्रोक्योरमेन्ट करें । टोटल प्रोक्योरमेन्ट के लिए यह जरूरी है कि हम गांवों की जनता पर निर्भर करें । मैं चाहता हूं कि गांव-गांव में कमेटियां बनाई जायं । चार-चार और पांच-पांच गांवों की एक कमेटी बने, ब्लाकों की कमेटी बने और उसको यह अधिकार दिया जाये कि वह वहां से गल्ला खरीदे और फिर सरकार को दे । मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार से काम किया जाएगा तो इसका हर जगह बहुत बड़ा प्रभाव होगा ।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 1930-31 में एक बहुत बड़ा आन्दोलन चला । बारदौली के अन्दर एक बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया गया था और उत्तर प्रदेश के अन्दर भी लगान के सम्बन्ध में आन्दोलन चला था । सरदार पटेल का बारदौली आन्दोलन हमारे देश की आजादी के आन्दोलन को आगे बढ़ाने में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । इस आन्दोलन का कारण यह था कि किसानों को उनके गल्ले का उचित मूल्य नहीं मिलता था । किसान की स्थिति यह थी कि उसको अपना गेहूं चार आने मन या छः आने मन बेचना पड़ता था । बारदौली के अन्दर सरदार पटेल ने और उत्तर प्रदेश में पण्डित जी, टण्डन जी और पन्त जी ने लगान बन्दी का आन्दोलन चलाया था । इन आन्दोलनों ने हमारे देश के आजादी के आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया और किसानों का उनमें बड़ा सक्रिय सहयोग रहा । हमारे श्री गुलाबराव पाटिल जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसको सदन के सभी क्षेत्रों — कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग — इन सब का समर्थन प्राप्त हुआ है । इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि उस पर वह पूरी तरह से ध्यान दे । इस बात को हम जानते हैं कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव का जवाब देंगे तो उसके बाद यह वापस लिया जाएगा ।

[श्री हर्षदेव मालवीय]

लेकिन वास्तव में हम यह चाहते हैं कि मंत्रीमहोदय इस दिशा में कोई ठोस प्रयत्न करें और अपना उत्तर इस प्रकार से दें कि जिससे हम सब लोगों को सन्तोष हो । धन्यवाद ।

4 P.M.

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उपसभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव मेरे लायक दोस्त पाटिल साहब ने सदन के सामने रखा है मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं । मुझे एक बात आपकी मार्फत शिन्दे साहब से कहनी है, और वह यह है कि आज जिस तरीके पर अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री चल रही है उससे मैं एक बात समझ पाया हूं कि जिस तरह से किसान का प्रोफेशन है तो बहुत उत्तम लेकिन समाज ने उसको बड़ा इन्फीरियर मान लिया है, तो यही हालत है हमारे अग्रिकलचर मिनिस्ट्री की । मैं समझता हूं, अग्रिकलचर मिनिस्ट्री की पूरी बात अभी देश में चल नहीं पा रही है । अग्रिकलचर मिनिस्ट्री में मंत्री जी की इफिशियेंसी को मैं डाऊट नहीं करता; वे तो बहुत पुराने, घुटे हुए, इन्सान हैं; नीयत पर भी डाऊट नहीं करता क्योंकि अग्रिकलचर मिनिस्टर हमारे 3 हैं, तीनों किसान हैं, सभी किसान हैं, लेकिन बड़ी अक्लमन्दी के साथ जो मिनिस्ट्री को आर्गेनाइज करते हैं उन किसानों को बनिया भी साथ-साथ बना दिया — फूड एण्ड अग्रिकलचर । फूड एण्ड अग्रिकलचर इक्ठ्ठा होने से यह किसी दूसरे का तो कुछ छीन के ला नहीं सकते उपभोक्ता के लिए, फिर किसान का ही छीनकर उसको दे देते हैं । एक तरफ इनकी पापुलेरिटी का सवाल है, अग्रिकलचर मिनिस्ट्री की, कि लोगों को सस्ता माल मिले; बतौर फूड मिनिस्टर की कोशिश यह है कि लोगों को सस्ता माल मिले और बतौर अग्रिकलचर मिनिस्टर यह चाहते हैं कि देश में पैदावार ज्यादा बढ़े । तो असल हालत यह हो गई कि सारी की सारी मिनिस्ट्री बड़ी कन्फ्यूज्ड है, इनको खुद पता नहीं कि वे करें क्या ? (*Interruption*) तो मैं समझता हूं अग्रिकलचर मिनिस्ट्री में खुद बड़ा कन्फ्यूजन है कि बतौर फूड मिनिस्टर वह क्या ऐक्शन करें और बतौर अग्रिकलचर मिनिस्टर वह क्या ऐक्शन करें । तो मैं आपकी मार्फत प्रार्थना करूंगा कि अग्रिकलचर मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री अलग-अलग होनी चाहिए ।

श्री रणबीर सिंह : मिनिस्टर भी न्यारे होने चाहियें ।

श्री सुलतान सिंह : और उनके मिनिस्टर भी अलग होने चाहियें क्योंकि कोई तो ऐसा रहे जो किसान के लिये लड़ सके, कोई ऐसा आदमी रहे जो किसान की बात कर सके और मैं समझता हूं इस बजट में अग्रिकलचर मिनिस्टर की बात शायद सुनी नहीं गई । पता नहीं सुब्रह्मण्यम साहब इनसे ज्यादा पैनी अंगरेजी बोलते हैं इसलिये भी गड़बड़ होती है, वरना कार की कीमत गिरी, रेफरीजरेटर की कीमत गिरी, पंखे की कीमत गिरी, बिजली के सामान की, दूसरी चीजों की कीमत गिरी । या तो बाबू जगजीवन राम और शिन्दे साहब कहीं उधर बैठे रह गये जब बजट बन रहा था । और अगर वे थे तो मुझे ताज्जुब होता है फिर ट्रैक्टर के लिये अग्रिकलचर मिनिस्टर ने क्यों नहीं लड़ाई की, इनपुट्स की कीमत के लिये अग्रिकलचर मिनिस्ट्री क्यों नहीं लड़ी या तो अग्रिकलचर मिनिस्ट्री ने हाथ उठा देना चाहिये कि हमारी कुछ चलती नहीं, और अगर चलती है तो किसान के काम में कोताही करना, यह अग्रिकलचर मिनिस्ट्री सबसे बड़ा गुनाह कर रही है ।

उपसभापति महोदय, ताज्जुब होता है कि हर तरफ नजर जाती है लेकिन जो इस देश की आय में, इस देश की संपत्ति में, इस देश की इकानामी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको इग्नोर कर दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो वह चम्पारन में किसान के घर से शुरू की थी । रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने अगर किसी को भगवान बताया है तो मंदिर-मस्जिद में भगवान नहीं बताया है । रवीन्द्र नाथ कहते हैं अगर भगवान किसी को देखना है तो किसान के रूप में भगवान है । लेकिन आज आप उस भगवान के पैर काटते हो चले जा रहे हैं और इससे देश उजड़ जायेगा और मिट जायेगा । मुझे इस बात का दुःख होता है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कारों की कीमत कम करा सकता है, टी० वी०सेटों की कीमत कम करा सकता है, लेकिन एग्रिकलचर मिनिस्टर अपनी एग्रिकलचर इकौनौमी को बचाने के लिए ट्रैक्टर और डीजल की कीमत तथा ट्रैक्टरों के टायरों की कीमत को कम नहीं करवा सकता है । मोटर साइकिलों के टायरों की कीमत कम हो गई है, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रकों की टायरों की कीमत कम नहीं हुई । ट्रकों के टायरों से उपभोक्ताओं को अनाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी कीमत कम नहीं हुई । किसान जिस ट्रैक्टर से खेती करता है उसके टायरों की कीमत कम नहीं हुई और ट्राली की टायरों की कीमत कम नहीं हुई । ताज्जुब तो इस बात का है कि इतनी चीजों के दाम कम होने पर भी एग्रिकल्चर मिनिस्टर किस लाइन पर सोच रहे हैं ?

कल शिन्देजी ने अपना व्यान दिया था और उसको सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि वे ग्राम और बार्ले के लिए सपोर्ट प्राइसेस देने वाले हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि वह सपोर्ट प्राइसेस बनिये के घर चली जायेगी तब दी जायेगी या किसानों के खेत में जब यह चीज होगी तब दी जायेगी ? अगर दस दिन के बाद भी सपोर्ट प्राइस का एलान किया गया तो सब बनिये के घर चला जायेगा और इस तरह की जो नीति होगी वह ठीक नहीं होगी। सब लोग सरकार की नीति के प्रति शक करेंगे। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश का चना बाजार में आने लग गया है और राजस्थान में भी चने की फसल कटने लग गई है। बार्ले भी मार्केट में आनी शुरू हो गई है। अगर आज आप इन चीजों सपोर्ट प्राइस का एलान कर देते हैं तो इससे किसानों को राहत मिल सकेगी। अगर आपने दस दिन या एक महीने के बाद सपोर्ट प्राइस का एलान किया तो वह सब बनिये के घर में चला जायेगा और किसान को उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं एग्रिकलचर मिनिस्टर साहब यह जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में कोई पोजिटिव डेट बतलाइये कि किस दिन से आप सपोर्ट प्राइस लागू करने वाले हैं ताकि किसान उस तारीख तक अपने माल को अपने पास रख सके ?

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस बात को बड़े जोरों से कहा जाता है कि इस साल तो हमारे देश में बम्पर क्राप हो रही है। यह जो बम्पर क्राप है, वह भारत देश के लिए है, किसान के लिए नहीं है। किसान जब भरपूर फसल करता है तो उस साल उसके अनाज के भाव नीचे चले जाते हैं। जिस साल उसकी फसल कम होती है उसको अनाज बेचने के बाद भी दूसरी जगह से कर्जा लेकर अपना भरण पोषण करना पड़ता है। किसान को तो जब भरपूर फसल होती है तब भी उसको कोई फायदा नहीं होता है और इस तरह से वह हमेशा ही डेट में रहता है। जब बम्पर क्राप होती है तो कोई भी उसके अनाज का ज्यादा पैसा नहीं देता है और इस तरह से बम्पर क्राप उसके लिए कोई माने नहीं रखता है और इसका नतीजा यह होता है कि वह हमेशा ही सूखे और ड्रौट की हालत में रहता है।

बार्ले जैसी चीज की बढ़िया बीयर बनती है और यूरोप के मार्केट में उसकी बहुत बड़ी मांग है। आज बार्ले के दाम हमारे यहां 34-40 रुपया क्विन्टल है और जब कि उसका भूसा जो होता है वह 32 रुपया प्रति क्विन्टल बिकता है। तो मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम बार्ले का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ? छोटे छोटे कारखानेदार जो चीज तैयार करते हैं सरकार उनके एक्सपोर्ट करने की पहिले से ही फिक्र करती है, लेकिन वह बार्ले के लिए मार्केट तलाश नहीं करती है। आज बार्ले के लिए मार्केट नहीं है, यह ताज्जुब की ही बात है। पिछली बार जब आलू की भरपूर फसल हुई थी और आलू सस्ते भाव पर बिका उस समय भी सरकार ने इसको एक्सपोर्ट करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। इस साल भी आलू की बहुत अच्छी फसल हुई है और उसके दाम गिरते ही चले जा रहे हैं। सरकार ने जब फसल तैयार थी उस समय तो उसको एक्सपोर्ट करने का प्रबंध नहीं किया। जब काफी आलू कोल्ड स्टोरेजों में चला गया तब उसने इसको एक्सपोर्ट करने का प्रबन्ध किया। इसका नतीजा यह होगा कि इसका फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बिरला बार्ले को एक्सपोर्ट तो करेंगे लेकिन करेंगे उस वक्त जब बार्ली बनिये के घर में होगा। चने की दाल का एक्सपोर्ट तो करेंगे लेकिन उस वक्त करेंगे कि जब वह बनिये के घर में होगा तो मुझे दुख होता है यह देख कर कि किस तरह से हमारी मिनिस्ट्री चल रही है। मैं तो कहूंगा कि पहली बात तो यह होनी चाहिए कि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को अलग अलग होना चाहिए। जब तक यह दोनों इकट्ठा है तब तक यह एग्रीकल्चरिस्ट को खा कर अपना नाम पैदा करती रहेंगी कि हम ने सस्ता माल दे दिया। क्योंकि उन का इंटेरेस्ट है इसमें कि वह सस्ता माल दें। इस के लिये फूड मिनिस्ट्री अलग हो और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अलग हो। वह फूड खरीदें और बेचें और यह पैदा करते रहें। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इन्होंने अच्छा बीज दिया, नयी टेक्नीक आयी एग्रीकल्चर की उन्नति हुई लेकिन इस के बावजूद भी आज हालत क्या है। आज कोई बी एस सी का डिग्री होल्डर खेती करने को तैयार नहीं है। सारे देश में आप घूम आइये, चाहे वह कुलक हो या मार्जिनल फार्मर हो कोई एम० एस० सी० या बी० एस० सी० खेती करने को तैयार नहीं है और कोई बिरला या टाटा का बेटा नौकरी करने को तैयार नहीं है। अगर एग्रीकल्चर में कोई लाभ है तो बी एस सी अपने खेत में जा कर अधिक पैदावार क्यों नहीं करना चाहता। नौकरी तलाश करने के पीछे वह क्यों पड़ा हुआ है। आप लोग कहते हैं कि इतना हेवी इन्कम टैक्स लिया जाता है लेकिन उसके बाद भी बिरला और टाटा का बेटा नौकरी की तलाश नहीं करता और किसान का बेटा एम एस सी

[श्री सुल्तानसिंह]

और पी एच डी करने के बाद भी मेम्बर पार्लियामेंट के यहां चक्कर काटता रहता है कि उस को नौकरी दिलवा दो। हम कहते हैं कि तुम ने एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री ली है, तुम एक्सपर्ट हो खेत में जा कर काम करो, वह कहता है कि वहां जा कर क्या करेंगे। हमारे प्रोडक्शन का कोई दाम नहीं है। उस के बाद एक बैठा है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। पता नहीं उस में विदेशों के एजेंट हैं या क्या है या वह इस देश की पैदावार को गिराने के लिये ही बैठे हैं। मुझे ताज्जुब होता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन पर। हम चाहते हैं कि वह एक दिन तो हमारे साथ बैठे। मैं बार बार कहता हूं और परसों भी जब बोल रहा था तो मने कहा था कि वह मेरे साथ खेत पर चले और वहां साबित करे कि गेहूं की 105 रुपये की कीमत कैसे पड़ती है। लेकिन वह एक दिन भी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं और मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन अगर यह मानता है कि खेती लाभदायक सौदा है तो पांच सौ एकड़ का फार्म उन को दो और उस में से वे अपनी तनख्वाह निकालें और फिर एक एक चीज का दाम पैदा कर के बतायें कि क्या पड़ता है। कोई रिसर्च मत करो। सीधी सी बात है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से। दुख होता है यह देख कर कि एक तरफ हमारा बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है जिस से देश में आशायें जगी है, उम्मीदें बंधी है, और यहां हम कुछ किसान एम पी है, पीछे बैठे है, हम बोल नहीं सकते। बोलें तो किस के खिलाफ। इंदिरा जी से इतनी आशायें है, उन का इतना बड़ा नेतृत्व है और दूसरी तरफ जब हम गांव में जाते है तो लोग हमारा कपड़ा फाड़ते हैं। कहते हैं कि तुम नालायक हो। जब कार की, रेफ्रिजिरेटर की कीमत घटती है तो क्या तुम इस लायक भी नहीं कि ट्रेक्टर की कीमत को कम करा सकी। हम उन को क्या जवाब दें। कम से कम इस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से पूछा जाये। हमारे साथ वह गांव में चले या सुब्रह्मण्यम साहब चलें...

श्री अण्णासाहेब शिन्दे : मैं आप के साथ चलने को तैयार हूं।

श्री सुलतान सिंह : गांव में पता लग जायेगा कि वहां आप की अंग्रेजी कैसी चलती है। तो मुझे दुख होता है। कम से कम थोड़ा बहुत प्रेक्टिकल ज्ञान तो होना चाहिए। जब हम कार की कीमत घटा रहे हैं, रेफ्रिजिरेटर की कीमत घटा रहे है तो अगर हम ट्रैक्टर की कीमत भी घटा दें तो उस से देश को बहुत ज्यादा लाभ होगा कार की कीमत घटने के बजाय। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी कर के पहले तो फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकलचर मिनिस्ट्री को अलाहिदा अलाहिदा कर दिया जाय और ट्रैक्टर की कीमत कम दी जाए। किसान की पावर की कम कीमत करो और उसके इनपुट्स की कीमत कम करो और चने और बार्ली का एक्सपोर्ट करो। इस के अलावा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को जरा गांव में भेजो और उसको तनख्वाह मत दो और अगर तनख्वाह दो तो फूड मिनिस्ट्री से दो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मत दो। मुश्किल यह है कि एग्रीकल्चर के बजट में से एग्रीकल्चर कमीशन तनख्वाह लेता है और दूसरे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन तनख्वाह लेता है और 15 करोड़ की बात सुब्रह्मण्यम् साहब ने और की है और वह खर्च किसान पर नहीं होगा। चार या पांच एक्सपर्ट रखे जाएंगे और वे सर्वे करेंगे कि काश्तकारों के क्या क्या प्राब्लम है गांवों में।

हर स्टेट गवर्नमेंट के पास एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट है। तहसीलदार बैठा है, पटवारी हर गांव में बैठा है, ग्राम सेवक बैठा है। यह 15 करोड़ रुपये बांटने में कुछ लोगों को लाभ होगा, हम लोगों को कोई लाभ नहीं। हम तो कहते हैं कि पाजिटिव बात करो। बार्ले की कीमत तय करनी है या नहीं? चने की कीमत फिक्स करनी है या नहीं? करनी है तो कब तक करनी है। ये पाजिटिव बातें करनी चाहिए, उससे लाभ होगा। कमेटियां बैठा रहे हैं, यह सर्वे कर रहे हैं, वह सर्वे कर रहे हैं, इन बातों से क्या फायदा है। अगर आपके बस की नहीं तो हम करके दिखाते हैं। सीधी सी बात है। इतना ही कहकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[The Vice-chairman (Shrimati Purabi Mukhopadhyay in the Chair.]

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Madam, I am thankful to you for calling me to reply to this very interesting debate. At the outset, I would like to thank Shri Gulabrao Patil for bringing this Resolution for debate in this House and great stalwarts from all sides have participated in this debate. It has been a very interesting and educative debate for me. Though I have been listening to debates in the past for many many years, this debate was really very lively. The reason is obvious. There

is a very sincere feeling in the minds of the hon. Members that agriculture and its interest should be safeguarded with vigilance and with all sincerity in this country. So, as far as emotions and feelings are concerned, I am entirely one with the sentiments expressed on the floor.

Before I make my submissions, I would like to make one or two propositions or statements. Madam, the Government of India attaches great importance to agriculture in our economy and we are well aware of even the experience elsewhere in the world. For instance, Malaviyaji referred to the experience of the United States of America. Now, the United States of America has become an industrial power and a lot of developments have taken place there. But basically, the American economy developed because agriculture was supported and strengthened and the interests of agriculture were safeguarded. Similarly, if we look into the history of Japan from the restoration of Meiji Dynasty 1860 onwards, we will find that the then Governments there—we are not concerned with the political aspects—gave a lot of emphasis to agriculture and agriculture was allowed to develop. A lot of protective measures were taken and that is why Japan today has become one of the dominating industrial and economic powers in the world. We are well aware of that. Madam, the present policy-makers in India are also very conscious of this problem because, as you are aware, the world food economy is deteriorating. If countries like India, China or Russia who have a very large chunk of population inhabiting this part of the globe have food difficulties, then there will be difficulties in the entire world. Day by day, world food stocks are going down. If we do not adequately protect the interests of agriculture, if we continue to be deficit and if we are required to depend on imports, then some countries in the world may find themselves in a very difficult situation. The Government of India will not allow such a situation to develop. Therefore, we are very clear about the role of agriculture in the Indian economy not only from the point of view of developmental economy, not only from the point of view of industrialisation of the country, not only from the point of view of providing employment to our millions of people but also from the point of view of immediately safeguarding our national interests and feeding the millions of our people both in rural and urban areas. So, on this, I don't think we have really any different approaches or different views. And I would put it to the hon. Members for their consideration. This is the point I wanted to tell you. And I am not saying that the Government of India's policies are hundred per cent right and there may not be any scope for improvement or correction. For instance, Shri Sultan Singh criticised us in very strong terms and I understand his feelings also. But the point which I would just like to put is as to how the trends of production are emerging in India, the way the production has started coming up, the very fact why the situation arose with which the hon. Members are concerned. The reason is that massive surpluses have started emerging in our agricultural economy. Madam, would this situation have come about, if the Government of India had not adopted appropriate policies in support of agriculture ? We had many, many good seasons in the past and also very good rainfall years. But even then, the production never came to 114 million tonnes or 115 million tonnes. In 1965-66 and 1966-67, we had 72 and 74 million tonnes of production. The production graph is going down only when there are very adverse climatic situations and some setbacks. Even then, the graph is much higher. The very fact that it is coming up is due to the reason that the Government is trying its level best to see that appropriate agricultural policies are formulated and agriculture is extended necessary support. And I would submit that there can be scope for improvement. That is why I said that this debate is very educative for me because there can be scope for improvement, there can be scope for providing correctives here and there. But, as far as general policy is concerned, I would submit that it is because of Government of India's very right understanding of the problems of agriculture, despite

[Shri Annasaheb P. Shinde.]

resources being very scarce in our country —and we are poor country, we have limited resources and there are conflicting demands from various sectors—the Government of India is making very large funds available for the development of agriculture. For instance, there was some criticism from Shri Goray that this whole Budget is urban—oriented. Now, I do not want to go into the problems of the Budget because the Finance Minister would be in a position to meet his point. Suppose we look into the provision for power and for fertilizers, it is meant for providing necessary support to agriculture. Madam, I would like to submit that modern agriculture today is closely inter-linked with the modernisation of the economy and industrial development. Agriculture today is not the agriculture of old days. Modern agriculture requires all the infra-structural support, and the support of science, the support of technology, the support of modern transport system, and the support of modern storage system. And unless physics is developed, we cannot go into the soil physics, unless the chemical industry is developed, we cannot organise large-scale chemical and fertilizer industries. And this is so much inter-linked. And, for instance, Shri Sultan Singh strongly referred to tractors. I appreciate his sentiments because the draft power problem in this country is very, serious and very, very difficult. Therefore, we have to see that proper means of cultivation are provided. And our experience is that where the labour is likely to be displaced we will have to be a little judicious and cautious. But our experience is that tractors do not replace the labour. Actually they help productivity. Some of these matters will have to be given considerable thought. I am not trying to pick up a quarrel in regard to these matters. But there should not be any fear or apprehension in the minds of the hon. Members as if the Government of India is completely letting down the agricultural sector, as if these aspects are not given due attention. For instance, I would like to submit that the whole Budget generally veered round to the one focal point of remunerative prices to the farmers. I would like to come to this point a little later. How have we been supporting agriculture ? For instance, within the last six or seven months, the Government of India revised the fertilizer prices three times. Now, I am not saying that there is no need to further reduce the prices or that there is no need to again go into the matter. The point is that many things were beyond the control of the Government of India. All the hon. Members are so knowledgeable and they know how the energy crisis developed in the world. Naphtha is the basic raw material for urea and you know how the prices of Naphtha skyrocketed in the world. This fertiliser or urea, we were purchasing in the international market because still we are not able to produce enough to meet the requirements from the domestic production. Naturally, we were importing to the tune of 40 per cent or so. My Ministry with the help of the Supply Ministry was purchasing urea in the International market at the rate of Rs. 500 or Rs. 600 per tonne. The price of this urea at one stage went up to Rs. 3,700 a tonne. Some of our purchases were made at about Rs. 3,000, or Rs. 3,200, or Rs. 2,700, or Rs. 2,800 per tonne. This urea, which we were purchasing in the international market at this price, we were selling in the Indian market at Rs. 2,000 per tonne. If you will look into the Budget figures of the Government of India, you will see how much support had to be provided for this purpose. The Government of India incurred a loss of Rs. 280 crores only for providing fertiliser to farmers in one of these years. I am not happy that Rs. 2,000 was a good price and all that ; I am not justifying that but because of these factors beyond the control of the Government and the world wide energy crisis this situation developed. But, now, fortunately for world agriculture, the fertiliser prices in the international market are coming down. But we have still in our stock large quantities which were purchased at a time when prices were very high. The Government of India revised the prices downward three times during the last six

to eight months. The prices have been revised and there has been such a substantial reduction in the case of PTO 5, particularly diammonium phosphate. In this case there has been a reduction of about Rs. 800 to Rs. 900 per tonne. In the case of urea it has not been very substantial but even there it has come down from Rs. 2,200 to Rs. 1,750. In the case of muriate of potash it has come down from Rs. 1,220 to Rs. 900 per tonne. The Government of India is very well aware of the problem and that is why the approach of the Government of India is to reduce the import prices. I think the hon. Members will realise that taking into consideration the present situation in the country, the economic situation in the country, all of us are struggling to meet the situation and you all extended your help and generous support to the Government of India. The Government of India was facing the inflationary situation and inflationary trends in the economy. The economy was going out of hand and at one stage one thought as if it had become almost unmanageable and even the prices of agricultural commodities had gone up by 80 to 85 per cent. This was not a desirable situation. These were distortions in the economy. Now we want the farmers to get remunerative prices, reasonable prices but I do not think that the hon. Members expect that the farmers should get prices which are out of proportion or out of tune with the economic condition or stability of this country. I do not think this is what they have in mind. Therefore, what the Government of India, all the State Governments and all of us were concerned about was how to check inflation. This is perhaps one of the greatest successes in the world which we have achieved. Even many powerful Governments in the world have not succeeded in checking inflation. It is the Government of India, under the leadership of Shrimati Gandhi, which has succeeded in controlling inflation and restoring stability of prices. So, in the present set of circumstances, I do not think that anybody has in mind that the prices should be increased. But the efforts of all of us should be to see how to reduce the cost of production. Indian farmers' interest can be protected only by one approach and that is by reducing the cost of production and by maintaining price stability. I have moved into a very large number of rural areas in the country. I have met a very large number of knowledgeable farmers. They mentioned to me a number of their grievances. They always say: Reduce the cost of inputs and we have no grievances against the Government of India's procurement prices, etc. So, our whole effort should be to see how we can reduce the prices and the Government of India's effort is to see how the prices of inputs can be reduced.

I have made a note of the suggestion made by Shri Sultan Singh about agricultural machinery. We can again consider it along with the Finance Ministry. Naturally we will have to approach the Government of India. The Government of India has to take a decision. Even others have to be convinced about our approach. These are matters which are not escaping our attention as such.

The other important point was raised about protection to farmers. I would like to submit that the farmers' interest will be best protected, if the productivity is raised and the farmers suffer if the productivity is very low. For instance, in Punjab, even in Haryana—such able Members are here and they know so much about agriculture—the farmers have succeeded in raising the productivity. As soon as productivity goes up, they are in a position to invest it again into agriculture and thus it gives further impetus to agriculture. Now, why is the same process not being carried out in the other States? Of course, some very good developments have been reported from West Bengal, but, Madam, I am referring here to the north-east region, Eastern U.P., Bihar, Assam, Orissa. In Bengal, fortunately, during the last two or three years, encouraging developments are taking place. Even then, much more needs to be done and productivity in this region needs to be

[Shri Anna saheb P. Shinde]

pushed up much higher so that if the productivity is raised, a proper price policy is adopted by the Government. I am quite sure that the forces of production will get released. Then see, Madam, how the Government of India is spending lavishly on irrigation projects. Everywhere, irrigation projects are on and the whole effort is to harness the water resources. Our country has got tremendous resources which need to be utilised so that production goes up and on all these, Government's investment policy is based. I do not think there is any misunderstanding on the Government of India's approach in regard to agriculture.

SHRI N. G. GORAY: You talked of huge amounts being spent on irrigation but is it not a fact that the gestation period of these schemes is very long?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: That is really one of the problems, I agree. The Government of India is very clear on this. What the State Governments do is—because our States are fairly large in size like almost a country in Europe and they have their regional problems—they start a number of projects at a time. The Government of India has been drawing their attention to this and saying that please, try to take up as few projects as possible so that they are expedited as soon as possible, so that the gestation period will be less. But the State Governments also have their problems, some regional problems and many other local problems and I do not think Gorayji is himself unaware of these problems.

SHRI RANBIR SINGH: What about the rate of interest? You get it at two per cent from the World Bank and advance the money to the State Governments at 7 or 8 per cent.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: You want me to reply to every problem, Finance Ministry's problems and other problems.

SHRI GULABRAO PATIL (Maharasntra): In western countries, you might be knowing, the period of recovery is thirty years, while here we want to recover within ten years and, therefore, the farmers have to suffer.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The Members are so knowledgeable. I will try to answer some of the important points. Even on this, I have something to say because in this matter, the Government's policy has been formulated in order to control the inflation. I think as soon as an element of stability is introduced in our economy, these points can be considered and some of the suggestions given here can be considered and, perhaps, even favourable decisions can be taken. But, in the present circumstances, I think, the uppermost and the most important point is the national interest, to control inflation and to see that money expansion is minimised to the extent possible.

SHRI RANBIR SINGH: It is better to have more production in the country rather than to have a higher interest rate.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: Then some hon. Members said that the present prices of procurement are very low. In fact, one of the hon. Members, I think it was Mr. Deorao Patil, made the statement that the Government of India, as such, mixed up procurement price and the minimum price. First of all, I would like to say that my Ministry used to get two types of reports: one support prices and the other procurement prices report and there was quite a wide gap between the support price and the minimum price. But we thought that market prices ruling everywhere were much higher than the support price. That was one reason. Secondly, we thought that we must give some adequate incentive to the farmers and, therefore, the purchases should not be made as far as possible at support price or the procurement price. We ourselves, in the Ministry, took the initiative. At that time, Mr. Jagjivan Ram, my senior colleague,

was in charge of the Ministry before Mr. Fakhruddin Ali Ahmed was elevated to the Presidency. At that time, the decision was taken that we should have only procurement price reports from the Agricultural Prices Commission. The Government have not tried to mix up the support price and the procurement price. Of course, one may have different views. Take, for instance, the statistics in regard to paddy. In 1967-68, the procurement price of paddy was—I am referring to the standard quality, the standard variety—Rs. 45; in 1968-69—Rs. 45; 1969-70—Rs. 45; 1970-71—Rs. 46; 1971-72—Rs. 47; 1972-73—Rs. 49; 1973-74—Rs. 70 and 1974-75—Rs. 74 for coarse variety. Progressively, the procurement price has gone up from Rs. 45 to Rs. 74 per quintal. What about the position in regard to wheat? Perhaps, public memory is very short. My valued colleague, Shri Ranbir Singh, may not remember it because it is convenient for him to forget many of these facts. What was the price of wheat in 1966-67? It was Rs. 54.

SHRI RANBIR SINGH: What about the prices of agricultural inputs and other industrial products? What about the cost of fertiliser?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The price of wheat gradually increased: Rs. 54, 65, 76 and so on. Even in 1972-73, the procurement price of wheat was Rs. 76 only. Even in 1973-74, the price was the same. Then, in 1974-75, we increased it to Rs. 105. There was one year in between when the support price was Rs. 80-85. Then, it jumped to Rs. 105. In this regard, we should also take into account the purchasing power of the people. Most of the people have low purchasing power. They spend almost 70—80 per cent of their family income on food. We have to be very careful when taking the decision. But even then, in order to protect the interests of the farmers, these decisions have been taken. I do not want to take the time of the House by quoting more figures. As far as wheat is concerned, I would like to make one submission. The procurement prices are announced by the Government of India. All foodgrains covered by procurement price cover 90 per cent of the foodgrains produced in this country like wheat, paddy, maize, bajra, jowar and even ragi. We have announced only yesterday that this time, we are even prepared to enter the market of gram and barley. As far as foodgrains are concerned, a wide network has been established in order to protect the interests of the farmers and to see that the middlemen are not allowed to exploit the farmers. It is for this reason that we banned the inter-State movement of foodgrains, particularly in the case of wheat. There is a complete ban in regard to wheat. We do not allow private parties and we do not allow middlemen to take advantage of the situation and exploit the farmers. As far as wheat is concerned, we have stopped that.

AN HON. MEMBER: What about the export of barley?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: In regard to exports, our general approach is this. First of all, food is a very favourable item. I would like to submit for the consideration of the hon. Members—I have said this on earlier occasions also—that foodgrain reserves in this country are more important than even the gold reserves. Therefore, whatever is available, we should mop up and store. Our first effort is to store the foodgrains. All the years are not going to be the same. We would like to ensure that our agricultural economy is strengthened so that the need for imports is eliminated. The position should be good not only in one year, but for many years to come. If we find that even after taking care of a year or two there is surplus, we can make calculations right now and arrive at certain conclusions. For instance, we exported potatos. We also exported cotton this year. The thrust is there already in that direction. This is a very healthy sign for our economy. It is a good sign that there is surplus in some of the important commodities of our agricultural

[Shri Annasaheb P. Shinde.]

economy. In future, this sector should form a very important instrument for earning foreign exchange. The surplus which is being generated would strengthen our economy. We would like to see that more and more surpluses are generated and we are in a position to export like United States and other countries. This would help us to earn foreign exchange and would also enable the farmers to market their produce at a reasonable price.

Many hon. friends have raised the question of parity between the prices of agricultural commodities and manufactured commodities. I know this is a highly controversial subject. Some hon. Members might even have different views on this. This is a very complex.

SHRI RANBIR SINGH: What is the storage capacity of the country and what quantity of foodgrains is likely to be purchased this year by the Government?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: After this statement I am going to say about it and I will complete my speech after that.

As far as the index for manufactured goods is concerned, if we take 1961-62 as the base of 100—the same base for agricultural commodities today—of course, up to December it is very clearly worked out from April to December, 1975 the index for manufactured goods is 247.6 while the index for agricultural commodities is 324.6. But I concede the point that this does not reflect the condition today because in the last three months there has been a considerable fall in the case of agricultural commodities. But, even then, according to whatever tentative figures I have worked out—this is subject to correction—I would like to mention that the edge is slightly in favour of agricultural commodities. If we take the base of 1962, while the index of manufactured goods is at 253.5, the index of agricultural commodities—as roughly worked out, subject to correction—is 275.1. So, there is still an edge in favour of agricultural commodities and the terms of trade are not entirely against agriculture.

Then, a very valid point was raised by Ranbir Singhji just now: he was interested in knowing what our storage capacity is and whether we are going to purchase all that would be offered by the farmers. Mr. Bhupesh Gupta, Nanasaheb Goray and a few other friends also raised this point. I would like to give, broadly, an assurance to the hon. Members that Government of India's efforts would be, whatever fair average quality grain is offered by the farmers in the country, whatever be our difficulty, no financial difficulty, no storage difficulty will be allowed to come in the way and we propose to step up our purchases. In fact, we have issued a communication to the State Governments that they should keep their machinery ready to step in immediately wherever the farmers are prepared to offer at the procurement price. We have also told the State Governments that if they are unable to cope up with the situation they may please inform us. We have now built up such a powerful organisation, the Food Corporation, and we are now in a position to enter any corner of the country and ensure that the surpluses which are brought by the farmers are purchased by the procurement agencies. There will be no financial difficulties. In fact, we have a general assurance from the Finance Ministry that all the finances required for procurement would be provided for. And storage problem will not be allowed to come in the way.

SHRI KALP NATH: In Eastern U.P. they are not purchasing, Sir.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I would only say that if hon. Members bring to our notice any difficulty in any particular area—in fact, this is a period when I would seek the co-operation of hon. Members—so that we are in a position to

know if there is any problem anywhere, we shall not hesitate to take necessary steps. As far as storage is concerned,...

SHRI GULABRAO PATIL: We should like to have an assurance from him.

SHRI KALP NATH: It is only Rs. 80 per quintal in the eastern part of U.P.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I can tell hon. Members that anywhere if the fair average quality wheat is offered at Rs. 105, we shall purchase everything that is offered.....(*Interruptions*).....I said there won't be any lack of financial support. Storage difficulty will not be allowed to come in the way. Today we are in a position when our whole machinery is geared to meet the situation.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: It should reach all parts of the country.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I feel completely confident because we have very closely reviewed the situation.

Then, the hon. Member, Shri Swaminathan of the ADMK has made a statement that there is a disparity as far as the price policy regarding wheat and rice is concerned. I do not agree with his statement. If he sits with me, I shall be in a position to convince him how the policy approach in regard to wheat and paddy is the same.

Then, a statement was made that potato exports may help only the traders, but I beg to differ from that statement. In fact, my Ministry has struggled so much; of course, it is an entirely new field and potato is a highly perishable commodity. We have asked the Food Corporation to purchase and that is why they have purchased and they are in the market. My information is that this year the distress which was there last year is not there and now, as we are getting more experience, next year we propose to enter the potato market in a very large way, based, of course, on our experience.

So our general approach would be to go on supporting, and extending the market in support of agricultural commodities, because I entirely agree with the hon. Members that agriculture is the backbone of our economy. If agriculture prospers, the country will become much stronger. And it has to be prosperous. This is broadly our approach. I entirely agree with the the sentiments expressed by the hon. Members....(*Interruptions*).

I wish Mr. Gulabrao Patil to be good enough to withdraw his Resolution.

SHRI GULABRAO PATIL: Let him give an assurance . . .

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I have already said that we are all prepared to purchase. Please withdraw your Resolution.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: You have not said anything about crop insurance.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We have pilot projects for insurance now already operating.

SHRI GULABRAO PATIL: Madam, Vice-Chairman, I am extremely grateful to the hon. Members who participated in the discussion on this Resolution. I am extremely grateful to them also for their whole-hearted support to this important Resolution.

I think all the hon. Members, irrespective of their parties, who participated in this discussion, were unanimous in supporting this Resolution. They were voicing the feelings of millions and millions of farmers of this country. I quite appreciate what Mr. Annasaheb Shinde has stated here, though I personally find that he always gives stereo-type replies on the floor of the House. At the same time, I do understand that it is not possible for the Government to come forward and do everything possible. But the feeling has been so vociferously voiced here particularly that prices of agricultural products are falling so steeply . . .

SHRI RANBIR SINGH : Crashing.

SHRI GULABRAO PATIL : They are crashing, and agriculturists are being crushed under these falling prices. We wanted that the Government should come forward and help the agriculturists. From that point of view, even Mr. Kalp Nath and Mr. Annasaheb Shinde or others who participated in this debate, particularly Mr. Ranbir Singh, Mr. Sultan Singh and Mr. Harsh Deo Malaviya,—all these persons were emphatic on one point that the Government should come forward to help the agriculturists. We do say that the Government is trying its best to reduce certain prices of fertilisers here and there. But what is the percentage? Madam, even after reduction of the prices of fertilisers, it is beyond the reach of the farmers to have these fertilisers and inputs even for more production.

As far as the availability of credit is concerned, Madam, much emphasis has been laid by almost all the Members that marginal farmers, small farmers, farmers having five acres and less, they are not in a position to get any credit from any institution. It is very sorry state of affairs when industrialists in this country can get finance at the rate of one per cent, amounting to crores and crores of rupees. Shri Annasaheb Shinde also said that farmers are the backbone of this country and that the entire economy rests on agricultural production. Every one has lip sympathy for the agricultural community. So much is expected to be done for them.

I would also like to urge upon the Government that as far as Budgets are concerned, if they are always going to be urban-oriented and city-oriented, you will be creating such imbalances that the farmers of India will not tolerate these things for long... (*Interruptions*) Shri Annasaheb Shinde should take up these matters, particularly the prices of fertilisers, inputs, insecticides, and so on. What is the price of seed in Maharashtra itself? It was being sold at Rs. 300 a quintal.

Adulteration was also there. I am myself a farmer cultivating some three or four acres of land and I know the difficulties that I am facing. Even though I am quite well known, I have got so many contacts, I cannot get whatever is required as far as production is concerned. What about the poor farmers? Therefore, I would urge upon Annasaheb Shindeji to see that if Government wants more production, they have to come forward to see that the morale of the farmer is kept intact, rather it is boosted up. Otherwise you cannot take them for granted because Annasaheb also thinks that we cannot go on strike. I will only give you one instance which took place in the 1942 movement. In a place in Walva taluk, Sangla district, under the leadership of Nana Patil, ex-M.P., when the underground workers' movement was there, all the milk supply was stopped to the city only because there were some informants who were givng information to the police. When it was stopped for two or three days, not a litre, not even a tea-spoon-ful of milk was available.

AN HON'BLE MEMBER : What happened in Bardoli and Champaran ?

SHRI GULABRAO PATIL : I am coming to that. If Annasaheb Shinde and the Agriculture Ministry feel that a farmer will not run away from farms, I may tell him that the commonsense of the farmer has not gone.

AN HON'BLE MEMBER : He is not listening to it.

SHRI GULABRAO PATIL : He is a person having commonsense. The urban people may be happy that the foodgrains prices and prices of other agricultural commodities are coming down and, therefore, they can get these things at cheaper (rates and they can enjoy TVs and refrigerators. But at whose cost? Therefore, Mr. Annasaheb Shinde, I would like to ask you—Annasaheb is not listening to me ; I would urge upon him to see..... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Gulabrao Patil, you have a right to get a reply. The Minister has already replied.

SHRI GULABRAO PATIL : I would only request Mr. Shinde to see—Defence is quite safe in the hands of Bansi Lalji—that the farmer is safe and strong and let him have a better standard of living. Therefore, make plenty of inputs like fertilizers, seeds and other things available to him at a cheaper rate—tractors, agricultural implements, even credit. As far as long-term credit is concerned, I have been to so many foreign countries. When I made an enquiry, I was told that as far as their country was concerned, they were advancing long-term loans for a period of 30—35 years even at one per cent interest. Here droughts, floods and so many calamities are there. But, in spite of that, you are attaching the properties of these farmers and putting them to sale. But in the case of those income-tax payers whose arrears have not been cleared, what steps have been taken ? You are picking out some utensils and all that of the farmer and putting them to sale. He has to face so many things. Therefore, I would urge upon Shindeji that these things should be taken into considera ion. I know that he himself is an agriculturist. But, unfortunately, as Shri Sultan Singh said, he is caught between such persons like members of the Agricultural Prices Commission who do not know anything about agriculture. Persons knowing nothing about agriculture are deciding the fate of the farmers in this country. It is really a sorry state of affairs. Therefore, Annasaheb, we will expect you, Babuji and Shah Nawaz Khan to sit there. Why do you want some experts when you yourself are an expert ? I would urge upon you, as you have assured us, to take steps to see that whatever foodgrains and other articles are available, they come to the market and if the prices are falling, at least to see that the Food Corporation and all other instruments are energised, geared up in order to see that the prices do not come down so that at least the procurement prices are paid to the farmer immediately—and everywhere. That is the plea that I am making to you.

With these words, once again, I repeatedly thank all the Members who have participated in this debate, and I am quite sure that in future at least the farmers will not be made to suffer as they are suffering today. Once again, I thank Annasaheb and others. I withdraw my Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): I shall now put the amendments to vote. Amendment No. 1 is by Shri Nathi Singh and amendment No. 2 is by Shri Deorao Patil. None of them is here. Even then, it is put to vote. The question is :

1. "That at the end of the Resolution the following be added, namely :—

'based on a reasonable return to the growers keeping in view the the cost of agricultural inputs and is further of opinion that the same principles should govern the fixation of prices of industrial products so that a proper balance is maintained in the prices of agricultural and industrial products'."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

2. "That in the last line of the Resolution, after the word 'growers' insert the following words, namely :—

'taking into consideration the cost of production'."

The motion was negatived.

SHRI GULABRAO PATIL : Madam, I withdraw the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is:

"That leave be granted to Shri Gulabrao Patil to withdraw his Resolution moved on the 12th March, 1976."

The motion was adopted.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत : अभी पांच मिनट के करीब बाकी हैं इसलिये मुझे अपना प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दे दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : You can move your Resolution but it will fall through. There is no time.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अच्छा, रहने दीजिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 29th March, 1976.

The House then adjourned at fifty-seven minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th March, 1976.

MGIPRRND—2 RSS/76 Sec. III Day— 2-6-76—595